RNI No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : भोपाल/म.प्र./581/2021-2023
Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

वर्ष 24 अंक 01 05 सितम्बर 2023

जगत विज़न

कमलनाथ और शिवराज के बीच ऐतिहासिक सियासी संग्राम

चुनावी रंग में रंग गई कांग्रेस और बीजेपी

प्रदेश के इतिहास का सबसे रोमांचक चुनाव

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

निर्भीक पत्रकारिता

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
दिल्ली संवाददाता	नीरज दिवाकर
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय
विशेष संवाददाता	अर्चना शर्मा

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com
Website: www.jagatvision.co.in

मासिक द्विभाषी पत्रिका वर्ष 24 अंक 01 05 सितम्बर 2023

(पृष्ठ क्र.-6)

- मंत्रिमंडल का विस्तार और बीजेपी की रणनीति 32
- तो क्या नीतीश सरकार में एक पत्रकार की जान 34
- राजनीति और आर्थिक विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान 36
- मणिपुरः हिंसा थमी जरूर है लेकिन संकेत शुभ नहीं हैं 39
- वीरांगना रानी दुर्गावती 42
- डेढ़ दशक में जन-सहयोग से विकसित राज्य के रूप में उभरा मध्यप्रदेश 44
- मध्यप्रदेश में कृषि और खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में मौजूद अपार संभावनाएँ 48
- नीति आयोग या अनीति आयोग? 52
- चिंता का विषय है जनसंख्या विस्फोट 59
- Global Warming its effects 62

दलित, आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को और कितना साफ करोगे शिवराज जी !

शिव के राज में आदिवासी और दलितों को मिलता है - पेशाब करना, मैला खिलाना, गाली देना, निर्वस्त्र कर परेड कराने जैसा सम्मान !

संपादकीय

महिला आरक्षण बिल पास होने का श्रेय सिर्फ मोदी को नही अन्य दलों को भी

लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद संसद के दोनों सदनों से लेकर विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत हो जाएगी। विधेयक के कानून में बदलने और क्रियान्वित होने के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए 181 और राज्य विधानसभाओं में 1374 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। महिला आरक्षण बिल को मोदी सरकार आने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तुरूप का इक्का मान रही है। सरकार का मानना है कि यह बिल देश की महिलाओं को शक्ति देगा। साथ ही जो काम पिछले वर्षों में कोई भी सरकार नहीं कर सकी वह हमने करके दिखाया है। हालांकि विपक्ष का भी अपना एक तर्क है। विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण की पहल और प्रयास कांग्रेस ने पहले भी किये हैं जिसमें कुछ कामयाबी भी मिली थी लेकिन यह बिल पूरी तरह से पास नहीं हो पाया था।

खैर, इसी साल पांच राज्य विधानसभाओं के अलावा 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। इसलिए नारी सशक्तिकरण के इस उपाय को महिला मतदाताओं के ध्रुवीकरण के साधन के रूप में भी देखा जा रहा है। देश में इस समय करीब 44 करोड़ महिला मतदाता हैं। हालांकि यह विधेयक दोनों सदनों से पारित हो भी जाता है तब भी इसे नई जनगणना और नए परिसीमन के बाद 2026 से लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसलिए आगे होने वाले चुनावों में इसे अमल में तो नहीं लाया जा सकेगा। भाजपा के लिए महिला मतदाताओं को आकर्षित करने का काम यह विधेयक अवश्य कर जाएगा। महिला आरक्षण लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी।

आपको बता दें कि स्व. राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में भी महिला आरक्षण बिल के लिए प्रयास किये गए थे लेकिन किन्हीं कारणों से यह बिल धरातल पर नहीं आ पाया। उसके बाद 09 मार्च 2010 में कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने इस विधेयक को राज्यसभा में पेश कर पास करा लिया था, लेकिन मनमोहन सिंह इसे लोकसभा से पारित नहीं करा पाए थे। जबकि उनके पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत था। इस सरकार को अपने ही सहयोगी दलों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था। सहयोगी गठबंधन के सांसदों ने पिछड़ी और मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने के प्रावधान के बहाने, इस विधेयक को अटका दिया था। अब जब मोदी सरकार इस बिल को लेकर खुद की खूब वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है तो उसे यह भी देखना चाहिए कि सिर्फ मोदी सरकार ने ही इस बिल को पास किया है इसमें विपक्ष के तमाम दलों का भी समर्थन मिला है तब जाकर यह बिल दोनों सदनों में पास हुआ है। श्रेय उन दलों को भी देना चाहिए। खैर, फिलहाल लोकसभा में 82 महिलाएं सांसद हैं। यह भागीदारी 15 प्रतिशत है। वहीं राज्यसभा में 29 महिला सांसद हैं, जो मात्र 12 प्रतिशत है। एक तिहाई आरक्षण लागू होने के बाद लोकसभा में महिलाओं की संख्या बढ़कर 181 और राज्यसभा में 73 हो जाएगी। हालांकि असमानता के ये हालत पंचायती राज लागू होने और उसमें महिलाओं की 33 और फिर 50 फीसदी आरक्षण सुविधा मिलने के बावजूद कायम हैं।

विजया पाठक

कमलनाथ और शिवराज के बीच ऐतिहासिक सियासी संग्राम

चुनावी रंग में रंग गई कांग्रेस और बीजेपी

प्रदेश के इतिहास का सबसे रोमांचक चुनाव

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है। यह आगाज राजनीतिक पार्टियों की ओर से प्रारंभ हुआ है। प्रदेश की दो प्रमुख पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव को लेकर कमर कस ली है। चुनावी सर्वे के बाद दोनों पार्टियों ने चुनाव को लेकर कसमकश प्रारंभ कर दी है। राज्य की दोनों प्रमुख पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनावों के लिए कैंडिडेट की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। कांग्रेस ने अभी उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं जारी की है, लेकिन उसकी तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच में प्रदेश में बीजेपी के नेताओं का पार्टी से मोहभंग भी हो रहा है और लगातार नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। पिछले 06 माह में बीजेपी के करीब 42 नेताओं बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इससे बीजेपी चिंता में है और डेमैज कंट्रोल करने में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस इस बीच राज्य में सात बड़े नेताओं के साथ राज्य के सात अलग-अलग इलाकों में एक जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। 2018 के चुनाव परिणामों को देखते हुए सारी तैयारियां की जा रही हैं। बीजेपी जहां सारे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर लोगों के बीच अपनी उपलब्धियों को गिना रही है वहीं कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालकर वर्तमान सरकार की नाकामियों को गिना रही है। दोनों ही पार्टियों को सिर्फ 2018 का परिणाम याद है। इससे पहले के परिणामों से कोई लेना-देना नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी जो रणनीति बनाई है उसमें 2018 के ही आंकड़े प्रमुख हैं। खामियों और खासियतों को ध्यान में रखकर रणनीति का काम किया जा रहा है। खासकर टिकट वितरण में भी वही चुनाव को ध्यान में रखा जा रहा है। एक तरफजहां कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का चेहरा आगे कर चुनाव मैदान में उतर रही है तो बीजेपी अभी तो केवल मोदी के नाम पर चुनाव में उतरने का मन बना रही है। क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी हाईकमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा नहीं कर रही है। बीजेपी के कई कददावर नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ने से मुसीबत खड़ी हो रही हैं। पार्टी में मचा घमासान बीजेपी को परेशान कर रहा है। अब बीजेपी डेमेज कंट्रोल करने में जुटी है। दूसरी तरफ देखा जाये तो वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति बीजेपी की अपेक्षा बेहतर है। पूर्व सीएम कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी मजबूत भी हो रही है और एकजुट भी। पार्टी के सभी प्रादेशिक नेता एक स्वर में, एक संकल्प के साथ चुनावी मैदान में हैं। किसी भी प्रकार का मनमुटाव देखने को नहीं मिल रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में हुए 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 230 सदस्यों वाली विधानसभा में 41.02 प्रतिशत मत के साथ सिर्फ 109 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस ने उस चुनाव में भाजपा से थोड़ा कम यानी 40.89 प्रतिशत वोट हासिल करने के बावजूद भाजपा से 05 सीटें ज्यादा यानी 114 पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने उस समय सपा, बसपा और निर्दलियों के सहयोग से सरकार बनाई और कमलनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बने। हालांकि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के विधायकों के इस्तीफे के कारण कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई और शिवराज सिंह चौहान फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। इस बार के चुनाव में सबसे प्रमुख बात है कि कांग्रेस जहां कमलनाथ के भरोसे चुनाव मैदान में उतर रही है वहीं पहली बार बीजेपी प्रदेश में शीर्ष नेतृत्व के आसरे हैं। शिवराज के घटते कद के कारण बीजेपी में बैचेनी है तो कमलनाथ की लोकप्रियता की वजह से कांग्रेस आशांवित है। इसी बीच आम आदमी पार्टी भी पूरे 230 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी है, जो कहीं न कहीं समीकरण बिगाड़ने का काम करेगी।

विजया पाठक

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो गई है। राज्य में कभी चुनाव का ऐलान हो सकता है। जिसका अंदेशा दोनों प्रमुख पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी को है। यही कारण है कि दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी मूड में आ गई हैं। टिकटों का ऐलान होने लगा है। चुनाव आचार संहिता को लेकर सत्तासीन बीजेपी धड़ाधड़ फैसले कर रही है। राज्य में बीजेपी पूरे जोर-शोर के साथ कार्यक्रमों और योजनाओं का ऐलान कर रही है। चुनाव के समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सभी वर्ग याद आ रहे हैं। लाड़ली बहना योजना लाकर महिलाओं की साधने की कोशिश की जा रही है। कर्मचारियों के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। प्रत्येक दिन कोई न कोई पंचायत कर सभी को साधा जा रहा है। विभिन्न आयोजनों पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। इन योजनाओं या घोषणाओं के लिए पैसा कहां से आयेगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस समय तो बस ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को सत्ता जाने का डर माथे पर चढ़ गया है और ऐन-केन प्रकारेण सत्ता को बचाने की जुगत पर जुगत लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी अब शंका जता रहा है कि इस समय प्रदेश में पार्टी के प्रति माहौल उनके पक्ष में नहीं है। यही कारण है कि पूरा शीर्ष नेतृत्व मध्यप्रदेश में डेरा डाले हुए है। किसी न किसी आयोजन के बहाने प्रधानमंत्री या गृहमंत्री प्रदेश में शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो वह पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार के चुनाव में वह पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने वाली है। प्रदेश में मिली हुई सत्ता जाने के बाद इस बार कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए। माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार पीएम मोदी के चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है। जैसा कि बीजेपी

चुनाव के समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सभी वर्ग याद आ रहे हैं। लाड़ली बहना योजना लाकर महिलाओं की साधने की कोशिश की जा रही है।

कमल विरुद्ध कमलनाथ : विधानसभा चुनाव 2023 कमल विरुद्ध कमनाथ के बीच है, क्योंकि बीजेपी का सम्पूर्ण शीर्ष नेतृत्व चुनाव मैदान में हैं और रणनीतियां बना रहा है वहीं कांग्रेस की ओर से चुनाव की सम्पूर्ण बागडोर कमलनाथ के हाथ है। उन्हीं के हाथों में चुनाव प्रबंधन है।

अन्य राज्यों में करती आ रही है। प्रदेश में लंबे समय से बीजेपी की सरकार है जिस कारण से पार्टी को एंटी इनकंबेंसी का डर भी सता रहा है। यह भी तय माना जा रहा है कि इस बार विधानसभा के चुनाव कशमकश भरे होने वाले हैं। बाजी किसके हाथ लगेगी इसका पूवार्नुमान किसी को नहीं है। लिहाजा सत्ताधारी दल बीजेपी किसी तरह की चूक करने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ने का लगभग मन बना लिया है। राज्य में बीजेपी की लगभग दो दशक से सरकार है। बीच में लगभग सवा साल ऐसा आया था जब कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी। लंबे अरसे से सत्ता की

सत्ताधारी दल बीजेपी किसी तरह की चूक करने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ने का लगभग मन बना लिया है।

बांगडोर बीजेपी के हाथ में होने के कारण पार्टी को एंटी इनकंबेंसी की चिंता सता रही है। पिछले कुछ दिनों में पार्टी के अंदरूनी सर्वे भी पार्टी को खुश करने वाले नहीं रहे। उसके बाद से पार्टी ऐसी रणनीति पर काम कर रही है जिससे एक तरफ एंटी इनकंबेंसी के प्रभाव को रोका जा सके तो वहीं प्रधानमंत्री की छवि को आगे रख कर जनता को लुभाया जा सके। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन का प्रदेश में लगातार दखल बढ़ रहा है और यही कारण है कि वरिष्ठ नेताओं की राज्य में सक्रियता भी बड़ी है। पार्टी का मकसद जमीनी स्थिति का आंकलन करना और उसमें सुधार लाना है। इसके अलावा पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ ही प्रधानमंत्री

06 महीने में 42 बीजेपी नेताओं ने छोड़ी पार्टी, थामा कांग्रेस का हाथ

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं का लगातार पार्टी से होता मोहभंग सत्तारूढ़ दल के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसा कोई हफ्ता नहीं जा रहा जब भाजपा से कोई नेता कांग्रेस में नहीं जा रहा हो। ऐसे नेताओं की संख्या 42 के पार पहुंच गई है, जो आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए अच्छे संकेत तो नहीं है। इसमें ताज़ा नाम नर्मदापुरम इलाके के कद्दावर नेता और 02 बार के भाजपा विधायक गिरिजाशंकर शर्मा का है। इस साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के सभी दिग्गज नेता प्रदेश के लगातार दौरा कर रहे हैं। उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे बड़े नाम चुनावी साल में अपनी बैठकें और दौरे जारी रखे हुए हैं। वहीं सूबे के असंतुष्टों को मनाने का जिम्मा तमाम केंद्रीय स्तर के नेताओं को दिया हुआ है, इसके बवजूद पार्टी छोड़कर बीजेपी नेताओं का कांग्रेस ज्वाईन करने का सिलसिला नहीं रूक रहा है। कांग्रेस का दामन थामने वाले गिरिजाशंकर शर्मा भाजपा के स्थानीय विधायक और पूर्व विधानसभा स्पीकर सीताशरण शर्मा के सगे भाई हैं। गिरिजाशंकर ने पार्टी छोड़ने के पीछे पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी को बड़ी वजह बताया है। उन्होंने आरोप लगाए कि बीते 10 साल से अधिक समय से पार्टी उनकी उपेक्षा कर रही है। संगठन में नए लोग आ गए हैं, यह नए लोग पुराने लोगों को लगातार दरकिनार कर रहे हैं। पुराने नेताओं की पूछपरख नहीं की जा रही है और संगठन में भी कोई सुनने वाला नहीं है। गिरिजाशंकर शर्मा ही नहीं, बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस चुनावी साल में पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं।

भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले प्रमुख नेता- आदिवासी नेता और पूर्व सांसद माखन सिंह सोलंकी (बड़वानी), सेवड़ा के पूर्व विधायक राधेलाल बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री

कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी, आष्टा विधानसभा के जिला पंचायत सदस्य कमल सिंह चौहान, पूर्व विधायक राव देशराज सिंह जी के बेटे यादवेंद्र सिंह यादव (अशोक नगर), पूर्व सांसद कंकर मुंजारे की पत्नी पूर्व विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष अनुभा

नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे भी राज्य में बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की छवि को पार्टी आगे रखकर राज्य के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने का मन बना चुकी है। इसी के चलते पीएम मोदी के राज्य में प्रवास भी बढ़ रहे हैं।

साथ ही दोनों पार्टियों ने चुनावी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। बीजेपी

मुंजारे और उनके बेटे ने भी कांग्रेस ज्वॉइन की, पूर्व मंत्री सतना के बड़े अल्पसंख्यक नेता सईद अहमद, नरयावली विधायक प्रदीप लारिया के भाई हेमंत लारिया, हरदा में मंत्री कमल पटेल के सहयोगी रहे दीपक सारण, मध्यप्रदेश दुग्ध संघ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर रही प्रसिद्ध पर्वतारोही मेघा परमार, नीतू परमार नगर पालिका अध्यक्ष मुल्ताई बैतूल, पंकज लोधा, धार, समंदर पटेल, नीमच, अजुम रहबर इंदौर, रोशनी यादव, निवाड़ी, बैजनाथ सिंह यादव, शिवपुरी, वेदांती त्रिपाठी, ध्रुव प्रताप सिंह, विजयराघौगढ़, मलखान सिंह, भिंड, अवधेश नायक, दतिया,

शुभांगना राने, धार, नीरज शर्मा, सुरखी सागर, जितेन्द्र जैन गोटू, राजकुमार धनौरा सुरखी, राजू दांगी, दतिया, देवराज बागरी, सतना, वंदना बाग़री, सतना, शंकर महतो, बहोरीबंद (कटनी), बजरंग सेना, रघुनंदन शर्मा, रामशंकर मिश्रा, अरूण पाठक, उर्मिला मराठा, अम्बरीश राय, राजेन्द्र सिंह मुरावर, रणवीर पटैरिया, भंवर सिंह शेखावत पूर्व विधायक भाजपा, जिला धार, चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू राजा जिला सागर (02 बार झांसी से सांसद रहे सुजान सिंह बुंदेला के पुत्र), वीरेंद्र रघुवंशी, भाजपा विधायक कोलारस, शिवपुरी), छेदीलाल पांडे, शिवम पांडे कटनी, अरविंद धाकड़ शिवपुरी, सुश्री अंशु रघुवंशी गुना, डॉ. केशव यादव भिंड, डॉ. आशीष अग्रवाल गोलू, भाजपा के पूर्व गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता के भांजे, महेंद्र प्रताप सिंह, गिरिजाशंकर शर्मा, पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हो गये हैं।

आपको बता दें कि चुनाव के ठीक पहले इन नेताओं के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के चले जाने से कैडर वाली पार्टी कहे जाने वाली बीजेपी के सामने संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इसके अलावा जो नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनका भी क्षेत्र में प्रभाव है। ऐसे में बीजेपी के वोट भी उन नेताओं के साथ शिफ्ट होने का खतरा बढ़ गया है। वहीं, बीजेपी के अंदर मची इस भगदड़ से सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हो रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा के मुताबिक बीजेपी नेताओं को भी अब दिखने लगा है कि वहां अब उनकी पूछ नहीं इसलिए वो उस पार्टी में शामिल हो रहे है जो देश की सबसे पुरानी और सेक्युलर पार्टी है। एमपी में बीजेपी की लम्बे समय से सरकार है। लेकिन जिस तेज़ी से नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, उससे बीजेपी की स्थिति कर्नाटक जैसी ही दिखने लगी है, जहां चुनाव से पहले नेताओं में बीजेपी छोड़ने की होड़ लग गई थी।

सबलगढ़ में सिंधिया समर्थक छोड़ रहे बीजेपी- विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने चंबल के मुरैना जिले की 06 विधानसभाओं में से दो विधानसभा सबलगढ़ और सुमावली में

जहां महिलाओं, किसानों और युवाओं को लेकर लंबी-लंबी घोषणाएं कर रही है और इन वर्गों को साधने की पूरी कोशिश कर रही है वहीं कांग्रेस सत्ता में आने के बाद की सभी वर्गों को लेकर वादे कर रही है। 2018 जैसे कशमशक चुनाव परिणाम के मददेनजर दोनों पार्टियां अब किसी भी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर

भाजपा ने एक महीने पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सबलगढ़ विधानसभा में भाजपा अजीब संकट से घिरी है। सिंधिया समर्थकों के अलावा अन्य भाजपाईयों में पार्टी छोड़ने की होड़ सी मच गई है। फिलहाल हालात ऐसे हैं, इस भगदड़ को मैनेज करने के फेर में सबलगढ़ में भाजपा का चुनावी माहौल ही नहीं बन पा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने सबलगढ़ विधानसभा में सरल रावत को उम्मीदवार

घोषित किया है। सरला रावत के परिवार को भाजपा ने लगातार 10वीं बार टिकट दिया है। सरला रावत लगातार दूसरी बार भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं। उनसे पहले आठ बार सरला रावत के ससुर मेहरबान सिंह रावत को भाजपा ने टिकट दिया, जिसमें वह तीन बार जीते थे। बस इसी बात को लेकर सबलगढ़ भाजपा के नेता तितर-बितर होने लगे हैं और जो कांग्रेसी सिंधिया के साथ भाजपा में आए, उनका मन भी उचट रहा है। सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं में भाजपा छोड़ने की भगदड़ मची है। सिंधिया के कट्टर समर्थक पूर्व विधायक सुरेश चौधरी के बेटे व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष त्रिलोक चौधरी अपने भाई दीपक चौधरी के साथ कांग्रेस में चले गए हैं और टिकट पर दावेदारी करने लगे हैं।

भाजपा की मुश्किलें बढ़ा रहे सिंधिया- सिंधिया के विश्वसनीय संजय फक्कड़ बीते दिनों भाजपा को छोड़ आम आदमी पार्टी में चले गए। इस बात की पूरी संभावना है कि वह आप के टिकट पर सबलगढ़ से विधायकी का चुनाव लड़ें। सबलगढ़ के इन दो बड़े नेताओं के अलावा कई और नाम हैं, जो चुनाव आते-आते भाजपा की मुश्किलों में इजाफा कर सकते हैं। केवल सिंधिया समर्थक ही नहीं, बल्कि भाजपा के नेता भी पार्टी से किनारा करने लगे हैं।

सरला रावत की ननद ने छोड़ी थी पार्टी- सबलगढ़ के पूर्व मण्डल अध्यक्ष आनंद सिंह सिकरवार भाजपा छोड़ चुके हैं। झुण्डपुरा नगर परिषद की पार्षद और भाजपा उम्मीदवार सरला रावत की ननद ने भी पार्टी छोड़ दी थी, जिन्हें बड़ी मनुहार करके भाजपा में वापिस लाया गया है।

सबलगढ़ में ब्राह्मण समाज की नाराजगी- सबलगढ़ में पार्टी नेताओं में पहले से गुटबाजी व नाराजगी है। इसी बीच ब्राह्मण समाज ने भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल भाजपा के नेता व पूर्व मंडी अध्यक्ष के बेटे ने इंटरनेट मीडिया पर ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए अमर्यादित टिप्पणी कर दी। हालांकि इस मामले में आरोपित पर कई थानों में एफआइआर दर्ज हुई, पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया, लेकिन ब्राह्मण समाज की नाराजगी कम नहीं हुई। इस नाराजगी व विरोध के कारण भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए सिंधिया सबलगढ़ नहीं गए। सबलगढ़ में सभा की औपचारिकता हो पाई, जैसी बाइक रैली की योजना बनी वह नहीं निकल पाई।

बीजेपी ने अपनी रणनीति तय कर ली है। प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। संगठन स्तर पर कसावट शुरू हो गई है। तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जिताउ उम्मीदवारों की खोज परख भी प्रारंभ हो गई हैं। एक तरफ जहां बीजेपी अपने अंदरूनी सर्वे के आधार पर विधायकों के टिकट तय करने की रणनीति पर कार्य कर रही है वहीं

बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा भी नहीं बना पा रही माहौल

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अलग रखा गया है। मतलब उनको सामने न रखते हुए शीर्ष नेतृत्व को आगे किया गया है। कहा जा सकता है कि सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी एक बार फिर जन आशीर्वाद यात्रा के भरोसे है। यात्रा का ये फॉर्मूला पुराना है, लेकिन भाजपा ने इसमें रणनीति नई लगाई है। इससे पहले 2013 और 2018 के चुनाव में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा चुकी है, लेकिन इस बार 03 सितंबर से शुरू हुई। ये पहले वाली यात्राओं से बिल्कुल अलग यात्रा हैं। उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी का चेहरा थे। उन्होंने इस यात्रा की 95 दिन अगुवाई की थी। इस बार एक नहीं, पांच यात्राएं निकाल रही हैं, जो 17 से 21 दिन में प्रदेश की 230 में से 211 विधानसभा सीटों को कवर करेंगी। इनका शुभारंभ 03 सितंबर को चित्रकूट से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर दिया है। इस बार यात्रा के नए फॉर्मूले से बीजेपी को फायदा मिलेगा? इस यात्रा के पीछे क्या है बीजेपी का धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण? पिछली तीन जन आशीर्वाद यात्राओं में चेहरा रहे मुख्यमंत्री शिवराज को इस बार कमान क्यों नहीं सौंपी? यह ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।

पहली यात्रा- 03 सितंबर को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विंध्य क्षेत्र के चित्रकूट (सतना) से पहली यात्रा का शुभारंभ कर दिया। सीधी में पेशाब कांड हुआ था जिसके कारण विंध्य का ब्राह्मण वर्ग बीजेपी

रामपुरा तहसील में ग्रामीणों ने जनआशीर्वाद यात्रा पर विरोध स्वरूप पत्थरबाजी की।

कांग्रेस भी अब ऐसे प्रत्याशियों की खोज में लगी है जो अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर छबि रखते हों। दोनों प्रमुख पार्टियां 2023 के विधानसभा चुनाव में फूंक-फूंक कर कदम रखने वाली हैं क्योंकि हालात बता रहे हैं कि इस बार टक्कर 2018 जैसी ही होने वाली है। टांके की इस टक्कर में जिस भी पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में गलती नहीं की वह पार्टी सत्ता पर काबिज हो जायेगी। सत्ता और

से नाराज चल रहा है। जानकार कहते हैं कि नड्डा से यात्रा का शुभारंभ कराकर पार्टी इस बड़े वर्ग को साधना चाहती है। दरअसल, नड्डा हिमाचली ब्राह्मण हैं। विंध्य में ब्राह्मणों का वर्चस्व है। यहां की राजनीति में उनका प्रभाव भी ज्यादा है। विंध्य क्षेत्र में 30 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 23 सीटें ऐसी हैं, जहां ब्राह्मणों की आबादी 30 फसदी के करीब है। यदि प्रदेश की बात करें तो सूबे में 10 प्रतिशत से ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं। विंध्य, महाकौशल, चंबल और मध्य क्षेत्र पर गौर करें तो यहां की 60 सीटें ऐसी हैं, जहां ब्राह्मण हार-जीत तय करते हैं।

दूसरी यात्रा- दूसरी यात्रा मालवा के नीमच से 04 सितंबर को शुरू हुई। इसे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें यह जिम्मेदारी जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए दी है। नीमच और मंदसौर में पादीदार, राजपूत-ठाकुरों की तादाद ज्यादा है। दो विधानसभा सीटों नीमच और मंदसौर पर बीजेपी विधायकों दिलीप सिंह परिहार और यशपाल सिंह सिसोदिया का कब्जा है। सूत्रों का कहना है कि इस इलाके में करणी सेना प्रभावी है। इसका एक धड़ा बीजेपी से नाराज चल रहा है। हाल ही में मनासा में मुख्यमंत्री शिवराज को काले झंडे दिखाने का प्रयास भी हुआ था। ऐसे में बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है।

नीमच में जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान चल रहे वाहनों पर लोगों ने तोड़फोड़ की।

विपक्ष दोनों ही चुनाव को हल्के में नहीं ले रहे हैं। सत्तासीन बीजेपी सरकार को एंटी एंकम्बेंसी का डर सता रहा है और पिछली कमलनाथ सरकार के कामों से लोगों के मन में जो पिछली सरकार की छबि बनी है उससे डरी हुई है। कमलनाथ भी अपने 18 माह के कार्यों को लेकर चुनावी मैदान पर उतरे हैं। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव में काफी कम वक्त बचा है। यही कारण है कि

तीसरी व चौथी यात्रा- तीसरी और चौथी यात्रा का 05 सितंबर को श्योपुर व मंडला में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुभारंभ किया। बता दें कि बीजेपी ने विंध्य-महाकौशल की 68 सीटों पर फोकस करने का मेगा प्लान तैयार किया है। जानकार कहते हैं कि बीजेपी के हाथ से आदिवासी वोट बैंक छिटकता जा रहा है। यही वजह है कि केंद्र और राज्य सरकार ने आदिवासियों पर डोरे डालने के लिए कई योजनाएं भी लागू की हैं। इसके बावजूद आदिवासी बीजेपी की पकड़ में नहीं आ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी आदिवासियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चेहरा बनाकर इस बड़े वोट बैंक को भाजपा के नजदीक लाने की कोशिश कर रही है। आदिवासी बहुल इलाके में 84 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 84 में से 34 सीट पर जीत हासिल की थी। 2013 में इस इलाके में 59 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। 2018 में पार्टी को 25 सीटों पर नुकसान हुआ है। जिन सीटों पर आदिवासी जीत और हार तय करते हैं, वहां बीजेपी को 16 सीटों पर ही जीत मिली है। यह 2013 की तुलना में 18 सीट कम है। अब सरकार आदिवासी जनाधार को वापस बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश में जुटी है।

पांचवीं यात्रा- पांचवीं यात्रा इंदौर संभाग के खंडवा से 06 सितंबर को प्रारंभ हुई। इस यात्रा को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरी झंडी दिखाई। जानकार बताते हैं कि खंडवा शहर से भले ही बीजेपी को पिछले चुनाव में फायदा हुआ हो, लेकिन इससे लगे जिले खरगोन में पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। इसी तरह बुरहानपुर में बीजेपी हार गई थी। यह इलाका महाराष्ट्र की सीमा से लगा है। अब बीजेपी इन इलाकों में जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से बढ़त लेना चाहती है।

शिवराज को नहीं बनाया यात्रा का चेहरा

इस बार जन आशीर्वाद यात्रा का प्रदेश के किसी भी नेता को चेहरा नहीं बनाया गया है। इसकी वजह यह है कि केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता कि राज्य के किसी नेता को आगे करने से पार्टी के भीतर आपसी मतभेद हों। जानकार कहते हैं कि पिछली यात्राओं में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चेहरा थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने रणनीति बदल दी है। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता का भरोसा है। जिसे बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी भुनाना चाहती है।

बीजेपी की जनआशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया गया है। मतलब साफ है कि इस बार शिवराज बीजेपी के चेहरा नहीं है। हालांकि प्रदेश में और कोई भी चेहरा नहीं है। शीर्ष नेतृत्व ही बीजेपी का चेहरा है।

दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह चुनावी मोड़ में आ गए हैं। दोनों ही दल एक-दूसरे पर हमलावर हैं। 2018 का विधानसभा चुनाव ऐसा चुनाव था जिसमें कांग्रेस को डेढ़ दशक बाद न केवल बढ़त मिली थी बल्कि सत्ता भी हासिल हुई थी, वहीं भाजपा डेढ़ दशक तक सत्ता में रहने के बाद बहुत कम अंतर से कांग्रेस से पीछे रह गई थी। पिछली बार

यात्रा में लोगों की भीड़ भी नहीं पहुंच रही है। बड़े-बड़े नेता भले ही यात्रा में शामिल हो रहे हैं लेकिन जिस उद्देश्य से यात्रा निकल रही है उसमें लाभ मिलने की उम्मीद कम है। इस समय के हालात को देखते हुए लग रहा है कि ये यात्रा भाजपा और सीएम शिवराज सिंह के लिए सुखद अनुभव नहीं है। यात्री के पहले ही दिन से पार्टी में कलह शुरू हो गई, जो 02 ही दिन में और बढ़ती दिखी। पार्टी से नाराजगी भरे बयान निकल रहे हैं। सीनियर नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। उमा भारती ने कहा कि कम से कम मैं यात्रा के शुभारंभ पर आमंत्रित किए जाने के योग्य थी। भले ही मैं वहां नहीं जाती लेकिन फिर भी मैं आगामी चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार करूंगी और वोट मांगूंगी। उमा भारती के बाद अब रघुनंदन शर्मा ने भी खुलकर नाराजगी व्यक्त की। उमा भारती के बाद रघुनंदन शर्मा का बयान बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकता है। उनका कहना है कि बीजेपी ने सीनियर नेताओं को दरकिनार कर दिया है। जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाये जाने पर रघुनंदन शर्मा भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा विक्रम वर्मा, सुमित्रा महाजन, कृष्णमुरारी मोघे, नारायण सिंह केसरी, कैलाश चावला, हिम्मत कोठारी, उमा भारती जैसे नेताओं को लेकर पार्टी ने मान लिया है कि इनका कोई धरातल नहीं है। सीनियर नेताओं का पार्टी में सम्मान नहीं बचा है। एमपी बीजेपी में कार्यकर्ता के प्रति प्रेम का अभाव है, इसलिये नेता और कार्यकर्ता आज बीजेपी से टूट रहा हैं। आज वेदना है कि कार्यकर्ता टूट रहा, अभी वक्त है पार्टी जाग जाए। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दोनों के पास कार्यकर्ता के लिए टाइम नहीं है।

यही वजह है कि मोदी की भोपाल, उज्जैन, श्योपुर, शहडोल और सागर में सभाएं हो चुकी हैं। इसी तरह अमित शाह ने मध्यप्रदेश चुनाव की कमान अपने हाथ में ली है। उनके प्रदेश में चार दौरे हो चुके हैं। खास बात यह है कि वे पब्लिक मीटिंग के अलावा संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारने की रणनीति को सख्ती से लागू करने की कवायद कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ एंटी इनकमबेंसी है। इससे निपटने के लिए बीजेपी ने किसी को चेहरा नहीं बनाया है।

यात्रा का हो रहा विरोध- यात्रा भले ही चुनावी माहौल बनाने के लिए किया जा रहा हो लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में विरोध हो रहा है। यात्रा वाहनों पर पत्थर टमाटर फेंकने के समाचार मिले हैं। लोगों को यह यात्रा रास नहीं आ रही है क्योंकि प्रदेश में इस समय बीजेपी के प्रति माहौल ठीक नहीं है। छतरपुर जिले में जैसे ही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा गुजर रही थी उसी टाइम पर चंदला विधानसभा के पास में ही गांव के लोगों ने यात्रा को लाठी डंडों के बल पर रोक लिया। यात्रा को रोककर ग्रामीणों ने कहा कि रोड नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। इसके अलावा भी यात्रा में लोगों का गुस्सा निकल रहा है। वहीं

कमलनाथ ने जो धोखा खाया है उससे सबक लेते हुए ही वह इस बार कोई गलती भी नहीं करने वाले हैं जिससे कांग्रेस को कोई नुकसान न हो पाये। बताया जा रहा है कि कांग्रेस इस बार बहुमत के आंकड़े 116 से आगे 150 का टारगेट लेकर चल रही है। चुनाव में अब केवल 03 महीने ही बचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आदिवासी गौरव दिवस पर मध्यप्रदेश प्रवास हुआ, इसी वर्ग से जुड़ी

कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को जनता का मिल रहा साथ

कांग्रेस प्रदेश भर में 7 आक्रोश यात्राएं निकालेगी जो 15 दिन में 11 हजार 400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस यात्रा का नेतृत्व अलग अलग स्थानों पर वरिष्ठ नेता करेंगे। कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में जन आक्रोश यात्रा की शुरूआत कर दी है। यह यात्रा प्रदेश की सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी। यात्रा के दौरान कांग्रेस के 11 वचनों को प्रचारित किया जा रहा है। प्रदेश के सात अलग-अलग स्थानों से यात्रा निकाली जाएगी। चुनाव अभियान के अंतर्गत कांग्रेस ने जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने के लिए जन आक्रोश यात्रा

रानी कमलापति के नाम पर भोपाल में रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया। राज्य में भाजपा की नजर आदिवासी वोट बैंक पर है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को आदिवासी इलाके में बड़ा नुकसान हुआ था। 47 सीटों में से भाजपा सिर्फ 16 सीटें जीत सकी थी और कांग्रेस 30 सीटों पर आगे रही थी। कुल मिलाकर भाजपा को सत्ता से दूर रखने में आदिवासी वोट की

निकालने का निर्णय लिया है। चुनाव से पहले जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस का बड़ा अभियान है। राज्य स्तर पर इसकी निगरानी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला कर रहे हैं तो लोकसभा पर्यवेक्षक विधानसभा क्षेत्रों में नजर रखेंगे। इसकी रिपोर्ट केंद्रीय संगठन को भेजी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि भाजपा से जो लोग कांग्रेस में आए हैं, उन्हें अपनी ताकत दिखाने का अवसर भी इस यात्रा के माध्यम से दिया जा रहा है। सभी नेताओं से कह दिया गया है कि वे अपने समर्थकों को साथ लेकर यात्रा को सफल बनाने में भूमिका निभाएं। दरअसल, इन नेताओं को जब पार्टी की सदस्यता दिलाई गई थी, तब यह दावा किया गया था कि इनके आने से न केवल भाजपा को बड़ा झटका लगेगा बल्कि कांग्रेस स्थानीय स्तर पर मजबूत होगी। जन आक्रोश यात्रा में इस दावे को भी परखा जाएगा और इस आधार पर यह भी निर्धारित होगा कि जो लोग चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, उनका जनाधार कितना है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी विंध्य क्षेत्र में जातिगत समीकरणों को देखते हुए अब पूर्व मंत्री दीपक जोशी का उपयोग करेगी। अभी यहां जन आक्रोश यात्रा निकालने की जिम्मेदारी पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को दी गई है। विंध्य क्षेत्र में ब्राह्मण भी कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रभावी भूमिका में है।

इसके प्रभारी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अरूण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और कमलेश्वर पटेल को बनाया गया है। ये सभी आवंटित जिलों में यात्रा की अगुवाई करेंगे। संगठन पदाधिकारियों का कहना है कि यात्रा के दौरान महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अनुसूचित जाति-जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्पीड़न, महिला अत्याचार, सरकार की घोषणाओं की स्थिति सहित अन्य विषयों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। साथ ही कांग्रेस द्वारा सरकार बनने पर जो 11 वचन लागू करने का वादा किया है, उन्हें प्रचारित किया जाएगा। यात्रा को सफल बनाने के लिए युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, सेवादल, मीडिया,

अहम भूमिका रही थी। भाजपा एक बार फिर इस वोट बैंक में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाह रही है। वहीं कांग्रेस की बात की जाये तो वह कर्नाटक चुनाव में मिली जीत से उत्साहित है। उसे लगने लगा है कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस वापिसी कर सकती है। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा की गई भारत जोड़ो यात्रा से मिले भारी जनसमर्थन से कांग्रेस

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सहित पार्टी के अन्य संगठनों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

भाजपा से कांग्रेस में आए नेताओं की परीक्षा- कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में भाजपा से कांग्रेस में आए नेताओं की परीक्षा भी होगी। सदस्यता लेते समय इन्होंने जो ताकत दिखाई थी, वह सभी को यात्रा में भी दिखानी होगी। इसके आधार पर ही तय होगा कि आगे इन्हें कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। कुछ नेता चुनाव दौड़ में भी हैं। उधर, पार्टी ने अभी केवल चंद्रभूषण सिंह बुंदेला और रघुनंदन शर्मा को प्रदेश महामंत्री बनाया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश मे यात्राओं का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस चुनावी राज्य मध्यप्रदेश में अक्रामक तेवर में नजर आ रही है। राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश में 150 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया तो अब कांग्रेस ने चुनावी सर्वे का हवाला देकर भाजपा को घेरने की तैयारी कर चुकी है।

क्या हैं उद्देश्य?- पार्टी के प्रदेश प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला और कमलनाथ ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 18 सालों की प्रदेश की बदहाली और बर्बादी का जनता में भाजपा राज के खिलाफजो असंतोष था, वो अब जनाक्रोश में तब्दील हो गया है। एक तरफजहां भाजपा राज के खिलाफ जनता में आक्रोश है तो दूसरी ओर कांग्रेस प्रति जनता में जोश दिखाई दे रहा है। जनता की इसी आवाज़ को सुनकर कांग्रेस 'जनाक्रोश यात्रा' का आगाज कर रही है।

कौन-कौन करेगा नेतृत्व?- जनाक्रोश यात्रा में प्रदेश की जनता कुल 11 हजार 400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस यात्रा को पूरा करने के लिए पार्टी के सात नेता नेतृत्व करेंगे। इन नेताओं में राज्य के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह 1600 किलोमीटर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरूण यादव 1700 किलोमीटर, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल 1900 किलोमीटर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल 1400 किलोमीटर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी 1400 किलोमीटर, कांतिलाल भूरिया 1700 किलोमीटर और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी 1700 किलोमीटर का सफर करेंगे।

का ग्राफ बड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। प्रदेश भर का दौरा कर कांग्रेस के प्रति माहौल बना रहे हैं और लोगों के बीच पहुंच कर वर्तमान सरकार की नाकामियों को उजागर रह रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में रही कांग्रेस की 18 महीनों की सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। वहीं, पार्टी इस महासंग्राम से पहले

सिंधिया समर्थक और मालवा के मंत्रियों पर कांग्रेस की नज़र

विधानसभा चुनाव शह और मात के इस खेल के खिलाड़ियों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों की घेराबंदी तेज कर दी है। 66 विधानसभा सीटों वाले मालवा-निमाड़ अंचल में कांग्रेस प्रदेश सरकार के दस मंत्रियों की घेराबंदी के लिए उनके विधानसभा क्षेत्रों में एक के बाद एक बड़े आयोजन, सम्मेलन और सभाएं आयोजित कर रही है। उद्देश्य एक ही है मंत्रियों को अपने गढ़ में ही उलझाए रखना ताकि वे अपने प्रभार वाले जिलों सहित आसपास के क्षेत्र में सक्रिय रहने के बजाय अपने क्षेत्र में ही उलझकर रह जाएं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक कहे जाने वाले मंत्रियों की सबसे तगड़ी घेराबंदी की जा रही है। दरअसल, 2020 में इन्हीं की

वजह से सत्ता गंवाने का दर्द कांग्रेसी अब तक नहीं भूले हैं। राज्य में मालवा-निमाड़ क्षेत्र से दस मंत्री हैं।

कुंवर विजय शाह

जगदीश देवड़ा

ओमप्रकाश सकलेचा

अपने समर्थकों को एक साथ रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पार्टी गारंटी पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, जो लोगों से जुड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में उसके लिए एक वरदान साबित हुआ। कांग्रेस ने 12 जून 2023 को राज्य में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की, जब पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जबलपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। राज्य के

तुलसी सिलावट, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और हरदीप सिंह डंग- ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी कहे जाने वाले मंत्री सांवेर से तुलसी सिलावट, बदनावर से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और सुवासरा से हरदीप सिंह डंग के क्षेत्रों में कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी सक्रिय हैं। सांवेर क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके विधायक पुत्र जयवर्धन सिंह के साथ ही प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी आयोजन कर रहे हैं। कभी प्रदर्शन तो कभी कथाओं के बहाने कांग्रेस नेता यहां सक्रिय हैं। इसी तरह राजवर्धन सिंह के विधानसभा क्षेत्र बदनावर और हरदीप सिंह डंग के सुवासरा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कई कार्यकर्ता सम्मेलन और सभाएं हो चुकी हैं। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे निमाड़ क्षेत्र को दोबारा हासिल करने के लिए पार्टी यहां पूरा जोर लगा रही है।

विजय शाह- खंडवा के हरसूद से आने वाले वनमंत्री विजय शाह के तीन दशक के कार्यकाल में कौन-कौन से काम नहीं हो पाए, इसका उल्लेख पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ हर सभा-सम्मेलन में कर रहे हैं।

प्रेम सिंह पटेल- बड़वानी में मंत्री प्रेम सिंह पटेल के विधानसभा क्षेत्र में सड़क, बिजली और मोबाइल नेटवर्क की समस्या दूर नहीं होने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता आदिवासी मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। यहां भी कांतिलाल भूरिया सहित अन्य वरिष्ठ आदिवासी नेता सक्रिय हैं। मालवा क्षेत्र के मंत्रियों पर भी कांग्रेस पदाधिकारी योजनाबद्ध तरीके से हमले कर रहे हैं।

जगदीश देवड़ा- मंदसौर-नीमच क्षेत्र से मंत्री जगदीश देवड़ा की टीम के सदस्यों पर गड़बड़ी के आरोप लेकर कांग्रेस पदाधिकारी लोगों तक पहुंच रहे हैं। यहां भी कमलनाथ और उनकी टीम मैदान संभाल चुकी है।

ओमप्रकाश सखलेचा- ओमप्रकाश सखलेचा पर क्षेत्र के लोगों से संपर्क नहीं रखने और निष्क्रियता के आरोप लगाते हुए कांग्रेस क्षेत्र में सम्मेलन कर रही है।

मोहन यादव- उज्जैन से मंत्री मोहन यादव पर अपनी निजी जमीन को मेला क्षेत्र से मुक्त कराने संबधी आरोप लगाते हुए घेराबंदी की जा रही है। कमलनाथ, पूर्व मंत्री सज्जनसिंह वर्मा यहां लगातार सक्रिय हैं।

इंदर सिंह परमार- शुजालपुर क्षेत्र में मंत्री इंदर सिंह परमार के क्षेत्र से ज्यादा भोपाल में सक्रिय रहने और अपने क्षेत्र को समय नहीं देने की बात उनके विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पहुंच रही है।

उषा ठाकुर- इंदौर जिले के महू क्षेत्र में मंत्री उषा ठाकुर के खिलाफ कांग्रेसी उनके बयानों और विकास नहीं करने जैसे मुद्दे को लेकर मैदान में है।

भाजपा सरकार में मालवा-निमाड़ क्षेत्र से जितने मंत्री है, उनके कार्यों को कांग्रेसी जनता के बीच ले जा रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया। न नए उद्योग लगे न गांवों में काम हुए।

मोहन यादव

इंदर सिंह परमार

उषा ठाकुर

लोगों को संबोधित करते हुए, प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की तर्ज पर पांच वादों की घोषणा की, जहां कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। पार्टी की ग्यारंटियों ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में काम किया था, जहां वह हाल ही में जीती थी। पार्टी ने सत्ता में आने के बाद वादों को पूरा करना भी सुनिश्चित किया था, इस प्रकार मतदाताओं को स्पष्ट

ग्वालियर-चम्बल : भाजपा के लिए बड़ी चुनौती

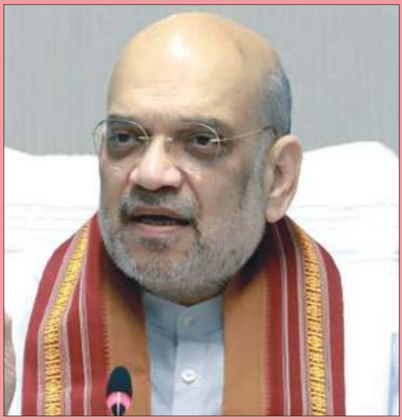

ग्वालियर चंबल अंचल में अपने गढ़ फतेह करना भाजपा के लिए नाक का सवाल बन गया है। कौन किस पर भारी पड़ेगा। कौन किसका किले ढहाएगा। यह 2023 के चुनावी रण में देखने को भी मिलेगा। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का फोकस उन इलाकों में है जहां 2018 में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव की कमान खुद अमित शाह ने उठा ली है। अमित शाह ने भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं तक लोगों तक पहुंचने को कहा है। पार्टी ने हाल ही में अपना सर्वे कराया था। इस सर्वे को लेकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के सर्वे में तीन इलाकों का फडबैक निगेटिव मिला है। अब इन इलाकों को साधने के लिए अमित प्लान बना रहे हैं। भाजपा के सर्वे रिपोर्ट में ग्वालियर-चंबल को लेकर निगेटिव रिपोर्ट आई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां भाजपा को बड़ा झटका लगा था। इस इलाके में विधानसभा की 34 सीटें आती हैं। लेकिन 2018 में भाजपा केवल 07 सीट ही जीत पाई थी। हालांकि 2020 में सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद यहां का समीकरण बदल गया था। उपचुनाव में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था। अब ग्वालियर-चंबल को साधने के लिए भाजपा ने नरेन्द्र सिंह तोमर को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया है। वहीं, सिंधिया केन्द्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इसी इलाके में

> **2018 के विधानसभा चुनाव में यहां भाजपा को बड़ा झटका लगा था। इस इलाके में विधानसभा की 34 सीटें आती हैं। लेकिन 2018 में भाजपा केवल 07 सीट ही जीत पाई थी। हालांकि २०२० में सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद यहां का समीकरण बदल गया था।**

संदेश है कि ये केवल वादे नहीं हैं, बल्कि इन्हें धरातल पर उतारा भी जा रहा है। आपको बता दें कि पार्टी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव के दौरान लोगों से किए गए वादों को पूरा किया।

2018 में हारी हुई सीटों पर बीजेपी का फोकस

मध्यप्रदेश में 2018 में हुए पिछले

आते हैं। इन नेताओं को जिम्मेदारी देकर पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश में है। विधानसभा चुनाव में ग्वालियर-चंबल की जंग बेहद रोचक मानी जा रही है। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के बड़े झत्रप इसी अंचल से आते हैं। खास बात यह है कि 2020 में हुए दलबदल में सबसे ज्यादा इसी अंचल के विधायकों ने पाला बदला था। यहां भाजपा जितनी मजबूत है कांग्रेस भी उतनी ही

दमदार है। लेकिन अंचल की पांच विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के गढ़ में तब्दील हो चुकी हैं। जिन्हें भेदना भाजपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। बताया जाता है कि ग्वालियर-चंबल अंचल में कांग्रेस के 05 ऐसे अभेद गढ़ हैं जिनको फतह करना भाजपा के लिए सपना बना हुआ है। 1990 से लेकर 2018 तक इन सियासी किलों पर भाजपा को शिकस्त मिली है, खुद एक बार शिवराज सिंह चौहान को यहां हार का सामना कर पड़ा है, यही वजह है कि इन किलों पर चढ़ाई करने के लिए इस बार भाजपा के अमित शाह खुद सियासी बिछात बिछाएंगे, क्योंकि इन गढ़ों पर जीत के सहारे ही भाजपा 2023 में कामयाबी का रास्ता बनाएगी। भाजपा के लिए ग्वालियर चंबल के इन 05 मजबूत सियासी गढ़ फतह करना सबसे बड़ी चुनौती है। शिवराज विधानसभा चुनाव में इन अभेद किलों में से एक किले राघौगढ़ पर शिकस्त झेल चुके हैं, ऐसे में इन किलों को भेदना भाजपा के लिए कहीं मुश्किल तो कही नामुकिन बना हुआ है। यही वजह है कि भाजपा अपने दिग्गजों को यहां मोर्चे पर तैनात करेगी। जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर नरोत्तम मिश्रा तक मोर्चा संभालेंगे। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व भी यहां एक्टिव होगा। राघौगढ़ का किला जीतना आज भी भाजपा के लिए सपना बना हुआ है। राघौगढ़ सीट दिग्विजय सिंह के परिवार की सीट मानी जाती है। यह कांग्रेस का ऐसा अभेद गढ़ है। जहां मुख्यमंत्री शिवराज को भी हार का सामना करना पड़ा था। 1990 से यहां कांग्रेस लगातार जीतती आ रही है। 1990 और 1993 में दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह यहां से विधायक चुने गए। वहीं 1998 और 2003 दिग्विजय सिंह जीते। 2008 में कांग्रेस के दादाभाई मूल सिंह जीते।

2020 में हुए दलबदल में सबसे ज्यादा इसी अंचल के विधायकों ने पाला बदला था। यहां भाजपा जितनी मजबूत है कांग्रेस भी उतनी ही दमदार है। लेकिन अंचल की पांच विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के गढ़ में तब्दील हो चुकी हैं। जिन्हें भेदना भाजपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है।

2013 के विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह ने इस सीट पर

विधानसभा चुनाव के नतीजे से सबक लेकर भाजपा इस बार उन विधानसभा सीटों पर खास तैयारी कर रही है। जिन सीटों पर 2018 में उसे हार का सामना करना पड़ा था। खासतौर से उन 103 विधानसभा सीटों पर फोकस किया जा रहा है, जिन पर वर्तमान में कांग्रेस, सपा, बसपा और निर्दलीयों का कब्जा है।

2013 के विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह ने इस सीट पर अपनी विरासत बेटे जयवर्धन सिंह को सौंप दी। जिसके बाद 2013 और 2018 में जयवर्धन सिंह यहां से जीते। भिंड जिले की लहार विधानसभा सीट ग्वालियर-चंबल में कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ मानी जाती है। लहार विधानसभा कांग्रेस का वो किला है, जिसे भाजपा बीते 33 सालों से भेद नहीं पाई है, इस सीट पर कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉ. गोविंद सिंह अंगद के पैर की तरह जमे हुए हैं। गोविंद सिंह ने लहार सीट पर सन 1990 से 2018 तक के सभी 07 विधानसभा चुनाव लगातार जीते हैं। वर्तमान में वह नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा सीट कांग्रेस भी कांग्रेस का अभेद किला बनी हुई है। इस सीट पर कांग्रेस के केपी सिंह बीते 30 सालों से अंगद के पैर की तरह जमे हुए हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 06 चुनाव में केपी सिंह ने लगातार यहां से जीत दर्ज करते हुए आ रहे हैं। 2008 में भितरवार सीट के अस्तित्व में आने के बाद से भाजपा के लिए इसे जीतना सपना बना हुआ है। इस सीट पर कांग्रेस के लाखन सिंह यादव जमे हुए हैं।

बीते एक दशक में शिवराज लहर और शिवराज मोदी लहर के बावजूद यहां पर भाजपा भितरवार में कांग्रेस के लाखन सिंह यादव को शिकस्त नहीं दे पाई है, 2013 और 2018 में इस सीट पर कद्दावर नेता अनूप मिश्रा शिकस्त झेल चुके हैं। 2008 से लाखन सिंह यादव ने लगातार तीनों चुनाव जीते हैं। ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट पर पिछले डेढ़ दशक से कांग्रेस का कब्जा है। 2008, 2013 और 2018 के तीन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की इमरती देवी जीत दर्ज कर कब्जा जमाया है। 2020 के उपचुनाव में भी डाबरा सीट कांग्रेस के खाते में गई। कांग्रेस के सुरेश राजे ने भाजपा के टिकट पर उतरी इमरती देवी को हराया। इन किलों के मजबूत इतिहास को समझने के बाद इन सीटों पर इस बार भाजपा चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की नजर है। भाजपा के आला नेताओं ने मंथन किया है, जिसमें तय हुआ है कि बूथ लेवल पर इन सीटों पर पार्टी को मजबूत किया जाना शुरू किया है। इस बार इन सीटों पर उम्मीदवार भी अमित शाह की मोहर लगने के बाद ही तय होंगे। ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर का कहना है कि पार्टी की नजर में सभी सीटे प्रमुख है, लेकिन जहां पार्टी हारी है, उन पर विशेष फोकस कर काम किया जा रहा है। यही नहीं इन पांच किलों पर लगातार जीत हासिल करने वाली कांग्रेस कर्नाटक चुनाव नतीजों के बाद उत्साह से भरी है। कांग्रेस का दावा है कि इन गढ़ों पर कब्जा तो बरकरार रहेगा। साथ ही अब कांग्रेस भाजपा के गढ़ों को भी जीतेगी। कांग्रेसियों का दावा है कि माहौल भाजपा सरकार के खिलाफहै, लिहाजा कांग्रेस को ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। इस बार ग्वालियर चंबल अंचल में अपने गढ़ बरकरार रखना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगा। तो वहीं इन गढ़ों को फतेह करना भाजपा के लिए नाक का सवाल बन गया है।

आपको याद दिला दें कि इनमें से 39 सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवारों की पहली सूची पिछले महीने 17 अगस्त को ही जारी कर चुकी है। बताया जा रहा है कि विपक्षी दलों के कब्जे वाली बची हुई 64 सीटों पर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति कभी भी मुहर लगा सकती है। वैसे तो 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सिर्फ 109 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी,

चुनौतियां कांग्रेस में भी कम नहीं हैं

विधानसभा चुनाव कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए एकतरफा नहीं रहने वाले हैं। बीजेपी जहां कई मामलों को लेकर घिरी नजर आ रही है तो कांग्रेस भी इससे अछूती नही है। पार्टी के अंदर एकजुटता का अभाव, मीडिया में कांग्रेस की बेहतर छबि न होना, सरकार के विरोध में पकड़ का कमजोर होना, जनता के बीच पहुंच कमजोर, मुददों को बेहतर तरीके से न उठाना जैसे तमाम मुददे हैं तो कहीं न कहीं कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। आज कांग्रेस को जरूरत है कि वह चुनाव के इस मौसम में बहुत समझदारी से अपने आप को प्रदर्शित करें और सत्ता पक्ष को कुछ आवाज उठाने का मौका न दे। यह सच है कि यह ऐसा चुनाव होगा जिसमें कार्यकर्ता और संगठन की भूमिका पिछले चुनावों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। जिस भी दल ने बेहतर उम्मीदवारों का चयन किया और कार्यकर्ताओं की क्षमताओं का इस्तेमाल किया, उसके लिए सत्ता की राह आसान जरूर नजर आती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि चुनौतियां कांग्रेस के लिए भी कम नहीं हैं

मध्यप्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में इस समय कांग्रेस के 96 विधायक हैं, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी के पास 126 विधायक हैं। 04 निर्दलीय विधायक हैं, जबकि दो बसपा और एक सपा का विधायक है। कांग्रेस इस बार एमपी में करीब 80 वर्तमान विधायकों को टिकट दे सकती है, जबकि 20 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। जिन सीटों पर पार्टी बहुत कम अंतर से हारी थी, वहां उम्मीदवार नहीं बदले जाएंगे। कांग्रेस ने प्रदेश में कुछ ऐसे सीटों की पहचान की है, जहां पार्टी लगातार हार रही है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने ऐसी 70 सीटें चिह्नित की है, जहां वह जीत के लिए तरस रही है। इन सीटों पर वर्षों से बीजेपी का कब्जा है। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के भीतर एकजुटता बनाए रखने की है। राज्य में वर्ष 2018 में हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी और सत्ता पर कब्जा जमाया था, मगर पार्टी के अंदर ही हुई टूट के चलते कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री यानी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का आपस में तालमेल कैसा होगा। जो चेहरे हैं वो दशकों से चले आ रहे हैं जिसकी वजह से लोग बदलाव भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को कई दिक्कतों से भी निपटना है। कई ऐसे नेता हैं जिनसे पार्टी ने किनाराकशी कर रखी है या उन्होंने खुद पार्टी से किनाराकशी कर ली है।

लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के विधायकों के इस्तीफा देने और भाजपा में शामिल होने के बाद हुए विधानसभा उपचुनाव में 18 सीटों पर भाजपा को जीत हासिल हुई और राज्य के कुल 230 सदस्य विधानसभा में वर्तमान में भाजपा के पास 127 विधायक हैं। 2023 में पूर्ण बहुमत हासिल करने के लक्ष्य के साथ भाजपा उन 103 विधानसभा सीटों पर खास तैयारी कर

वादों के बीच कर्ज में डूबा मध्यप्रदेश

चुनावी साल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार एक के बाद एक बाज़ार से कर्ज़ उठा रही है। हाल में खबर सामने आई है कि शिवराज सरकार फिर से 500 करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। इससे पहले फरवरी महीने में शिवराज सरकार ने चौथी बार बाज़ार से ऋण उठाया था। चुनाव से पहले मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार आर्थिक संकट से गुजर रही है। प्रदेश का खजाना खाली है। सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके चुनावी साल में जनता को लुभाने के लिए नई घोषणाएं कर रही है और कर्ज लेने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब प्रदेश के साथ करीब 4 लाख करोड़ कर्ज हो गया है। वहीं राज्य के हर नागरिक के उपर 40 हजार रुपये का कर्ज हो गया है।

500 करोड़ का नया कर्ज

मध्यप्रदेश सरकार ने आरबीआई से फिर 500 करोड़ रूपये का कर्ज लिया है। इसे 12 साल के टेन्योर में चुकाना होगा। इस पैसे को सरकार 22 सितंबर 2035 तक चुकाना होगा। मध्यप्रदेश सरकार इस साल छह महीनों में अलग-अलग तारीखों पर 12 बार कर्ज ले चुकी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून और सितंबर में सरकार ने आरबीआई से लोन लिया है। हालांकि, 2023-24 का वित्तीय वर्ष शुरूहोने के बाद सरकार का यह तीसरा कर्ज है।

घोषणाएं पूरी करने के लिए कर्ज

नया वित्तीय वर्ष शुरूहोने तक एमपी पर लगभग 3.32 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज था। इसके बाद लगातार कर्ज लेने से

रही है जहां पर वर्तमान में विपक्षी खेमे के विधायक है। इस बार आम आदमी पार्टी भी विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है। मध्यप्रदेश विधानसभा में वर्तमान में भाजपा के 127 विधायक, कांग्रेस के 96 विधायक, 4 निर्दलीय विधायक, दो बसपा के और एक समाजवदी पार्टी का विधायक हैं। 230 विधानसभा सीटों वाली इस विधानसभा में

शिवराज सरकार ने कब कितना लिया कर्ज

25 जनवरी 2023	- 2000 करोड़
02 फरवरी 2023	- 3000 करोड़
09 फरवरी 2023	- 3000 करोड़
16 फरवरी 2023	- 3000 करोड़
23 फरवरी 2023	- 3000 करोड़
02 मार्च 2023	- 3000 करोड़
09 मार्च 2023	- 2000 करोड़
17 मार्च 2023	- 4000 करोड़
24 मार्च 2023	- 1000 करोड़
29 मई 2023	- 2000 करोड़
14 जून 2023	- 4000 करोड़
12 सितंबर 2023	- 1000 करोड़

21 सितंबर 2023 यानी सरकार 500 करोड़ का कर्ज ले रही है

यह आंकड़ा 04 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुका है। इसके बाद भी मध्यप्रदेश में घोषणाओं का सिलसिला जारी है। इसे पूरा करने के लिए सरकार लगातार कर्ज ले रही है।

हर व्यक्ति पर 40 हजार का कर्ज

वित्तीय वर्ष की शुरुआत में एमपी सरकार पर 3 लाख 32 हजार करोड़ के आसपास का कर्ज था। अब यह आंकड़ा 4 लाख करोड़ के करीब पहुंचने की कगार पर है। इसके लिए एमपी सरकार हर साल कर्ज पर 20 हजार करोड़ रुपये ब्याज देती है। चुनावों के पहले सरकारों के लिए वादा करना और घोषणाओं से मतदाताओं को लुभाना आम बात हो गई है। हर एक पार्टी ऐसा ही करती है। मध्यप्रदेश

भी इससे अछूता नहीं है। प्रदेश के कर्ज में हुई ताबड़तोड़ बढ़त तो यही बताती है कि अंततः और कर्ज लेकर ही इन योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। पिछले वर्ष ही प्रदेश का कुल कर्ज बोझ सवा तीन लाख करोड़ से अधिक हो चुका है। मौजूदा वर्ष में भी 55 हजार करोड़ रुपए कर्ज प्रस्तावित है जिससे प्रति व्यक्ति पर कर्ज का भार बढ़कर लगभग 50 हजार रुपये हो जाएगा। भले ही तर्क दिया जावे कि यह कर्ज केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर है मगर प्रश्न यह उठता है कि कर्ज की रकम बजाय ऐसे संसाधनों में लगाने के जिनके रिटर्न से अदायगी संभव हो सके, राजनीतिक रेवड़ी बांटने में किया जाना कहां तक उचित है? सुप्रीम कोर्ट चुनाव के पहले के रेवड़ी कल्चर पर गहरी नाराजगी जता चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी कह चुके हैं कि वोट के लिए मुफ्त सुविधाएं बांटने वाला कल्चर आर्थिक विकास के लिए बहुत महंगा पड़ेगा और युवाओं के वर्तमान को खत्म करके भविष्य को अंधेरे में धकेल देगा। जो लोग मुफ्त की सुविधाएं बांटने का ऐलान करते हैं, वे बुनियादी ढांचा बनाने और देश के भविष्य को संवारने में कोई योगदान नहीं देते। मगर लगता है कि उनकी अपनी पार्टी समेत कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। यह कल्चर भले ही राजनीतिक हित साधता हो और निम्नतम गरीब तबके को तात्कालिक फायदा पहुंचाता हो मगर वर्ग भेद भी उत्पन्न करता है

116 विधायक होना जरूरी है।

कांग्रेस में सर्वे में बड़ा दावा- चुनाव से पहले कई सर्वे सामने आए हैं जिनमें प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। साथ ही बीजेपी 55 सीटों से भी कम पर सिमट रही है। पिछले 5 महीनों में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर 06 अलग- अलग सर्वे सामने आए हैं। सभी सर्वे में बीजेपी की सीटें लगातार घटती जा

आम आदमी पार्टी भी बिगाड़ेगी समीकरण

विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी पूरी दमखम के साथ उतर रही है। जो सियासी समीकरण को बिगाड़ने में पूरी भूमिका में रहेगी। निश्चित ही ज्यादातर सीटों पर आप हार जीत के आंकड़ों को प्रभावित करेगी। आम आदमी पार्टी ने सभी 230 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है और अगले 200 दिनों तक पार्टी अपने संगठन को मज़बूत करने से लेकर तगड़े उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनावों के माध्यम से 'एंट्री' ली। फिलहाल प्रदेश में उसके 52 पार्षद हैं और सिंगरौली से एक महापौर। इन चुनावों में आम आदमी पार्टी को छह प्रतिशत वोट मिलने से राजनीतिक विश्लेषक भी हैरानी में हैं। इतना ही नहीं आम आदमी पार्टी के समर्थन वाले लगभग 118 सरपंचों, 10 जिला पंचायत और 27 जनपद के सदस्यों ने भी चुनाव जीता है। इसलिए अब पार्टी ने विधानसभा की तरफ़ अपनी निगाहें टिका दी है। फ़लिहाल प्रदेश में आप के 3.5 लाख वॉलंटियर हैं और वो राज्य भर के 66 हज़ार बूथों तक अपना संगठन मज़बूत करने का अभियान चला रहे हैं। हालांकि आप में भी पार्टी छोड़ने का क्रम जारी है। हाल ही में आप के 10 पदाधिकारियों ने पार्टी से नाता तोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है।

रही हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के सर्वे में भी पार्टी बुरी तरह से हार रही है। ये सर्वे आने के बाद से मध्यप्रदेश बीजेपी में खलबली मची है और ये सुझाव भी मिला है कि 60 प्रतिशत बीजेपी विधायकों के टिकट काटे जाएं। इंटेलिजेंस का एक गोपनीय सर्वे लीक हुआ जिसमें बीजेपी को 80 से भी कम सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। कांग्रेस के जीत के दावे के कई कारण है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में भाजपा को पटखनी देने वाली कांग्रेस अब पूरे जोश से मैदान में है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कहते है 2018 के चुनाव से पहले मई में प्रदेश अध्यक्ष बना था। नवंबर में चुनाव थे।

मध्यप्रदेश में बीजेपी के पास नहीं है जिताऊ चेहरा?

बीते एक वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लगभग एक दर्जन बार मध्यप्रदेश का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के लगातार दौरों ने प्रदेश की भाजपा, सत्ता, सगंठन पर सवालियां निशान खड़ा कर दिया है। भाजपा के शीर्ष नेताओं के लगातार हो रहे दौरों से इस बात का आंकलन भी लगाया जाने लगा है कि प्रदेश में भाजपा के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जिसके नाम पर प्रदेश भाजपा जनता से वोट मांग सके। यही कारण है कि मोदी और अमित शाह लगातार प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। मोदी के इस दौरे की शुरूआत सितंबर 2022 में कूनो पालपुर से हुई थी। इसके बाद महाकाल कॉरीडोर का शुभारंभ, दो बार वंदे मातरम् ट्रेन का शुभारंभ और रीवा में पंचायती राज दिवस का आयोजन, शहडोल दौरा और हाल ही में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ। केंद्र सरकार के प्रमुख आयोजनों का मध्यप्रदेश में होना और उनमें शामिल होने मोदी का आना साफतौर पर इस बात की ओर इशारा करता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश भाजपा की स्थिति को लेकर शीर्षस्थ नेता भी खतरा महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफकेंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी मोदी की राह पर चलते हुए निरंतर प्रदेश के अलग-अलग दौरे कर भाजपा के सत्ता और संगठन को मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी और शाह के लगातार मप्र के दौरों को लेकर सियासी गलियारे में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि क्या इस बार भाजपा मोदी और शाह के चेहरे पर ही चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। क्या प्रदेश में ऐसा कोई जनप्रिय और लोकप्रिय नेता नहीं है जिसके चेहरे पर प्रदेश में भाजपा सत्ता पर कायम रह सके। अब देखने वाली बात यह है कि क्या शाह और मोदी के दौरों का परिणाम प्रदेश भाजपा को मिलेगा या फिर एक बार फिर मोदी और शाह को यहां से निराश होकर जाना होगा। मोदी, शाह सहित प्रदेश संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी विगत कई महीनों से विंध्य, महाकौशल पर अधिक फोकस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि विंध्य, महाकौशल दो ऐसे क्षेत्र हैं, जहां भाजपा को कमजोर बताया जा रहा है। यही कारण है कि प्रदेश संगठन इन क्षेत्रों पर अधिक फोकस कर रहा है।

मध्यप्रदेश में काफी लोग मुझे पहचानते नहीं थे मेरी कार्यशैली से वाकिफ नहीं थे परंतु आज ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश का हर वर्ग कमलनाथ को और कमलनाथ की कार्यशैली को जानता और पहचानता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और उसके बाद जिस तरह कांग्रेस को पहले हिमाचल विधानसभा चुनाव और फिर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्प्रेरक का काम

कर रही है जिससे कांग्रेस संगठन मोबाइलज हुआ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूरगामी असर हुआ है। राहुल गांधी ने जो नई कांग्रेस बनाई है, वह राहुल कांग्रेस है। राहुल गांधी की मर्जी से ही मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और कर्नाटक चुनाव में दोनों के बीच तालमेल दिखाई दिया। कर्नाटक और हिमाचल की जीत से कांग्रेस पार्टी एक पुर्नजीवन प्राप्त कर चुकी है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मध्यप्रदेश की जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाते हुए दिख रही है। चाहे वह भ्रष्टाचार का मामला हो या कर्मचारियों की मांगों का कांग्रेस इनको प्रमुखता उठा रही है। कांग्रेस ने अपनी पिछली गलतियों से सीखा है। इसलिए इस बार पार्टी नेतृत्व यह सुनिश्चित कर रहा है कि इस साल के अंत में होने वाले महासंग्राम से पहले कोई पार्टी छोड़कर न जाए। इस बीच कांग्रेस ने उम्मीदवार चयन पर काम करना शुरू कर दिया है। मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन के साथ-साथ चुनाव के लिए उम्मीदवारों को शार्ट लिस्ट कर रही है। पार्टी की स्क्रीनिंग प्रक्रिया से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि उम्मीदवारों का चयन उनके संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में जीतने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। राज्य की बीजेपी सरकार की विफलताओं पर

आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस को बढ़त मिली तो 15 साल बाद बीजेपी को सत्ता से दूर होना पड़ा। पिछले चुनाव में हुई चूक को भाजपा दोहराना नहीं चाहती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी वर्ग को पार्टी से जोड़ने के लिए पेसा कानून लागू किया है। आदिवासियों से जुड़ी तमाम योजनाओं, जनजातीय जननायकों की प्रतिमाएं लगवाने और स्मारकों का विकास कराने जैसे काम तेजी से शु डिग्री किए हैं। 15 नवंबर से मप्र में पेसा कानून प्रभावी होने के बाद सीएम खुद आदिवासी क्षेत्रों में जाकर पेसा जागरूकता शिविर लगाकर आदिवासियों से सीधे जुड़े। मप्र के 20

मध्यप्रदेश में कांग्रेस कर्नाटक की तर्ज पर स्थानीय मुद्दों को उठाने की रणनीति पर चल रही है। वहीं भाजपा के पास मजबूरी है कि उसके पास स्थानीय मुद्दों में उठाने के लिए कुछ होता नहीं है।

एक तरफजहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह विधानसभा स्तर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और वहां कार्यकर्ताओं को लामबंद कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच की समझ से कांग्रेस को बीजेपी के गढ़ वाले इलाकों सहित ग्रामीण इलाकों में जमीन हासिल करने में मदद मिल अभियान भी तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस का अभियान किसानों पर भी केंद्रित होगा, जहां यह वादा को पूरा करने में विफल बीजेपी सरकार की असफलताओं को उजागर करेगा।

आदिवासी समाज के वोटर पर निगाहें- मध्यप्रदेश की सियासत में इन दिनों समाज का सबसे पिछड़ा तबका यानी आदिवासी राजनीतिक दलों की जुबान पर है। प्रदेश की करीब 02 करोड़ से ज्यादा आदिवासी आबादी को लुभाने के लिए सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस के नेता जोर लगा रहे हैं। पिछले चुनाव में

जिलों के 89 ब्लाक आदिवासी बहुल हैं। इनमें सबसे ज्यादा इंदौर संभाग के 40 विकासखंड आदिवासी बहुल हैं। इसी वजह से लगातार हो रहे इन राजनीतिक कार्यक्रमों का केंद्र इंदौर ही है। दूसरे नंबर पर जबलपुर संभाग के 27 ब्लाक जनजातीय बाहुल्य हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो साल भर तक आदिवासी राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र इंदौर ही रहा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी इसी आदिवासी बाहुल्य इलाके में अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं। मध्यप्रदेश के 20 जिलों में कुल 89

विकासखंड आदिवासी क्षेत्रों में हैं। प्रदेश की लगभग 84 सीटों पर आदिवासी वोटर ही तय करते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट बताती है कि देश में 50 प्रतिशत या इससे ज्यादा जनजातीय आबादी वाले कुल 36,428 गांव हैं। आधी से ज्यादा आदिवासी आबादी वाले गांवों में मप्र देश में पहले नंबर पर है। एमपी के 7307 गांवों में आदिवासियों की आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा है। साथ ही आदिवासियों की बड़ी आबादी होने से प्रदेश की 84 सीटों पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक हैं। प्रदेश में 2013 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित इन 47 सीटों में से भाजपा ने 31 सीटें जीती थीं। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 15 सीटें आई थीं, लेकिन 2018 के चुनाव में भाजपा को इसी ट्राइबल बेल्ट से करारी हार मिली और वो सिर्फ16 पर ही जीत दर्ज कर सकी। कांग्रेस ने 30 सीटें जीती थीं और भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं आदिवासी वोटों के कारण ही 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी।

अन्य पार्टियां बिगाड़ सकती हैं सियासी गणित? मध्यप्रदेश में आम आदमी पार्टी की चर्चा शुरू हो गई हैं। यहां पर आप को तीसरी पार्टी के रूप में देखा जाने लगा है। आप प्रदेश में सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब सवाल उठने लगा है कि क्या आप प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी का सियासी गणित बिगाड़ सकती है। वैसे आप ने प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। मप्र में पहली बार आम आदमी पार्टी का मेयर बना है। सिंगरौली में आप प्रत्याशी रानी अग्रवाल ने भाजपा के उम्मीदवार को हराया। केजरीवाल 2023 के मप्र के चुनाव में दल-बल के साथ उत्तर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने भोपाल में आयोजित एक रैली चुनावी बिगुल फेंक्रते हुए घोषणा की कि पंजाब की तर्ज पर ही मप्र में अगर उनकी सरकार आई तो बिजली, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं का मुफ्त कर दिया जाएगा।

कमलनाथ बनाम शिवराज पर केन्द्रित चुनाव - मध्यप्रदेश विधानसभा

चुनाव कई मायनों में खास होने वाल है। क्योंकि इस बार न बीजेपी के पास और न ही कांग्रेस के पास कोई ऐसा मुददा है जिसे लेकर वह मतदाताओं के बीच जा सके। केवल घोषणाओं और गारंटी के बल पर दोनों पार्टियां चुनाव मैदान में हैं। मध्यप्रदेश में इससे पहले वाले चुनावों को देखें तो हर बार कोई बड़ा या प्रभावी मुददा रहा है जिसके बलबूते वह मैदान में कूंदी। लेकिन इस बार कोई लहर या मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है। 2003 के चुनाव में सड़क, पानी, बिजली और दलित एजेंडा जैसे मुद्दों पर जनता ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंक्रा था। 2008 के चुनाव में कांग्रेस गुटबाजी के चलते हारी। 2013 में कांग्रेस नेतृत्व वाली केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार के सत्ता विरोधी रुझान और देश में मोदी लहर के चलते कांग्रेस को प्रदेश की सत्ता से बाहर रहना पड़ा। 2018 में तस्वीर बदली और भाजपा को सत्ता विरोधी रुझान व कांग्रेस के किसान कर्जमाफ के नारे ने चुनाव हरा दिया। 2023 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर पिछले चार चुनावों से अलग रहने की संभावना है। इस बार कोई लहर या बिजली, सड़क, पानी जैसे मुद्दे नहीं हैं, जो चुनावी तस्वीर बन रही है उसमें कमलनाथ के 15 महीने बनाम शिवराज के 18 साल पर ही मतदाताओं की मुहर लगेगी। 2003 में जिन मुद्दों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, सरकार बदलने वाले वे सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं। वहीं इतिहास की बात करें तो बीजेपी के लिए 2008 का चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण था। शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता दांव पर थी, उमा भारती की भारतीय जनशक्ति पार्टी भी मैदान में थी। कांग्रेस की हार का कारण गुटबाजी बनी। 2013 के चुनाव में कांग्रेस को अपनी ही यूपीए गठबंधन की केंद्र सरकार की एंटी इनकंबेंसी का प्रदेश में सामना करना पड़ा। देश में मोदी लहर थी। 2018 में आरक्षण और एससी-एसटी एक्ट का मुद्दा हावी रहा। पदोन्नति में आरक्षण और एससी-एसटी एट्रोसिटी एक्ट का मुद्दा गरमाया हुआ था। जो संकेत मिले हैं, या जो ट्रेंड दिखे हैं, उससे साफ है कि दोनों ही पार्टियों के लिए 2023 का संघर्ष कड़ा रहने वाला है।

मंत्रिमंडल का विस्तार और बीजेपी की रणनीति

राजेन्द्र कानूनगो

प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के तीन विधायकों को आखिर मंत्री के रूप में शामिल करके अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर ही लिया। मंत्रिमंडल के विस्तार करने के साथ बीजेपी ने तीन महीने से भी कम समय में होने वाले चुनावों से पहले प्रदेश में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। राज्यपाल ने तीन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। पूर्व मंत्री, ब्राह्मण नेता और विंध्य क्षेत्र के रीवा से चार बार के विधायक राजेंद्र शुक्ला, महाकौशल क्षेत्र के बालाघाट से सात बार के विधायक एवं मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन और बुंदेलखंड क्षेत्र के टीकमगढ़ जिले के खरगापुर से विधायक राहुल लोधी ने मंत्री पद की शपथ ली। राहुल लोधी पहली बार विधायक बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव से लगभग 75 दिन पहले मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर पत्रकारों से कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद भी प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है। सीएम शिवराज के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में अब कुल 34 सदस्य हो गए हैं। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक यह संख्या 35 तक जा सकती है। राहुल लोधी बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती के भतीजे हैं। वहीं, बिसेन और लोधी दोनों अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। राजेन्द्र शुक्ला ब्राह्मण वर्ग के हैं। इनके मंत्रिमंडल शामिल होने से विंध्य क्षेत्र के मंत्रियों की संख्या चार हो जाएगी, जबकि बिसेन के आने से महाकौशल इलाके के मंत्रियों की संख्या दो और लोधी के जुड़ने से बुंदेलखंड के मंत्रियों की संख्या पांच हो जाएगी।बीजेपी सूत्रों ने कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की सिफ़ारिश पर यह कैबिनेट विस्तार किया गया है। शनिवार को किए गए विस्तार के बाद भी, कैबिनेट में एक और मंत्री के लिए जगह बची है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा कि शुक्ला को मंत्रिमंडल में शामिल करने से बीजेपी को विंध्य क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी, जहां पार्टी विधायक और एक मजबूत ब्राह्मण नेता

नारायण त्रिपाठी द्वारा समर्थित नया राजनीतिक दल विंध्य जनता पार्टी (वीजेपी) पहली बार चुनाव लड़ेगा। वीजेपी विंध्य क्षेत्र की सभी 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों में, बीजेपी ने विंध्य क्षेत्र में 24 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस केवल छह सीटें हासिल कर सकी थी। इस बार बीजेपी को विंध्य क्षेत्र में सत्ता विरोधी लहर से निपटना है। इसके अलावा, आम आदमी पार्टी भी वहां पैठ जमाने की कोशिश कर रही है। इसी तरह, बिसेन के शामिल होने से उन लोगों की नाराजगी दूर होने की संभावना है, जो महसूस करते हैं कि बीजेपी ने उनकी उपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि बिसेन से पहले महाकौशल क्षेत्र से केवल एक ही मंत्री था। पिछले विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा था। पिछले चुनाव में महाकौशल क्षेत्र की 38 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 24 पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी को 13 सीटें हासिल हुई थीं। एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार की झोली में गई थी। राहुल लोधी के शामिल होने से उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे बुंदेलखंड क्षेत्र में भी बीजेपी को फायदा होने की संभावना है। पार्टी ने पिछले चुनाव में 29 सीटों वाले बुंदेलखंड क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया था, उसे 15 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को नौ सीटों से संतोष करना पड़ा था। एक-एक सीट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की झोली में गई थी। बीजेपी ने 2003 में मध्यप्रदेश में कांग्रेस से सत्ता छीन ली थी, तब से दिसंबर 2018 से मार्च 2020 के बीच 15 महीने की अवधि को छोड़कर, जब कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में सत्ता में थी, बीजेपी राज्य में सत्ता पर काबिज है। जैसा कि सब जानते हैं कि 2018 के विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस ने 230 सीटों में से 114 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी 109 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। कांग्रेस ने निर्दलीय, बसपा और सपा विधायकों के समर्थन से कमलनाथ के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई थी। हालांकि, यह सरकार 15 महीने बाद गिर गई थी। इसका कारण लिखना जरूरी नहीं है, सब जानते हैं। इससे बाद ही भाग्यशाली शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी करने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ था। अब बीजेपी पुनः सत्ता में आने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यहां यह भी लिखना जरूरी है कि कांग्रेस भी कोई कमी नहीं रखना चाहती है और उसके दिग्गज रण नीति बनाने और उसे क्रियान्वित करने में जुटे हैं। अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो मुख्यमंत्री के दावेदारों में शिवराज के अलावा कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे। समय बताएगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजेगा?

2018 के विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस ने 230 सीटों में से 114 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी 109 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। कांग्रेस ने निर्दलीय, बसपा और सपा विधायकों के समर्थन से कमलनाथ के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई थी। हालांकि, यह सरकार 15 महीने बाद गिर गई थी।

तो क्या नीतीश सरकार में एक पत्रकार की जान की कीमत 20 हजार रूपये है?

भैरु सिंह राठौड़

अभी हाल ही में बिहार में एक पत्रकार विमल यादव की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जाता हैं कि विमल यादव एक विचाराधीन मुकदमे में अहम गवाह थे और उस मुकदमे का बहुत जल्दी फैसला आने वाला था। अपराधी इस बात से भलीभांति परिचित थे कि फैसला उनके खिलाफ आएगा तभी तो उन्होंने उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। सबसे बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात तो यह है कि मरने से पहले पत्रकार विमल यादव ने अपनी सुरक्षा हेतु पिस्तौल का लायसेंस लेने के लिए दो साल से जिला प्रशासन के यहां चक्कर लगा रहे थे पर उनको लायसेंस नहीं दिया गया। अगर प्रशासन द्वारा उन्हें लायसेंस दे दिया जाता तो शायद आज उनकी जान बच सकती थी। यह बात प्रशासन को भी कई सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। नीतीश कुमार की एक अलग बात है जो लोगों के जेहन में कांटे की तरह चुभ रही हैं और वो है अपने वोट बैंक के स्वार्थ की खातिर जेल में बंद सजायाफ्ता बाहुबली सांसद आनंद सिंह की समय सीमा से पहले रिहा कर देना जिनका की एक हत्या के मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है। इसका हिसाब किताब भी आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता जरूर करना चाहेगी। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि नीतीश सरकार के नुमाइंदों द्वारा मुआवजे के तौर पर विमल यादव की मौत पर केवल मात्र बीस हजार रूपये का चेक लेकर उसके परिजनों के पास पहुंचने का दुस्साहस किया जो नीतीश सरकार के डूब मरने जैसा है। तो क्या नितीश सरकार की नजर में लोकतंत्र के सजग प्रहरी एक

पत्रकार की जान की कीमत 20 हजार रूपए है? मात्र बीस हजार रुपए से किसी की जान की कीमत का आंकलन करने वाले नीतीश कुमार को मौत का दर्द तो तब होता जब अपराधियों की गोली से अपना करीबी कोई मौत का शिकार होता। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को तत्काल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि पूरा देश जानता हैं कि बिहार में शराबबंदी बिल्कुल पूरी तरह असफल रही है और अभी कुछ महीने पहले अवैध शराब कांड में सौ से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। बिहार के लोग अभी उस अवैध शराब की घटना को नहीं भूले होंगे शायद। और अभी कुछ दिन पहले अपराधियों द्वारा बिहार में एक दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और सुशासन बाबू सुशासन का ढोंग पीटते हुए नजर आ रहे हैं जो निहायत ही बेहद शर्मनाक है। बिहार में शराबबंदी

मात्र बीस हजार रूपये से किसी की जान की कीमत का आंकलन करने वाले नीतीश कुमार को मौत का दर्द तो तब होता जब अपराधियों की गोली से अपना करीबी कोई मौत का शिकार होता। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को तत्काल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।

बिल्कुल पूरी तरह असफल होकर फेल साबित हुई है और नीतीश कुमार एक असफल राज्य के मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। जिस नीतीश कुमार को अपना घर संभालना मुश्किल हो रहा है और वो प्रधानमंत्री बनने का ख़्वाब देख रहे हैं। नीतीश कुमार पहले अपना घर मजबूत करें फिर आगे की सोचें। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को कानून व्यवस्था के लचीलेपन को सहर्ष स्वीकारना होगा जो एक कड़वी सच्चाई है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार सता के नशे में चूर होकर अंधे बन गए हैं जो इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता इसका जवाब देकर उनके अहम् पर तगड़ा प्रहार करेगी। इसमें रति भर भी संदेह नहीं है। नीतीश कुमार ने अवसरवादी राजनीति की पराकाष्ठा को लांघ दिया है जो निकट भविष्य में उनके लिए नुकसानदायक साबित होगी क्योंकि यह वही जनता है जो किसी को अर्श से फर्श पर लाने में एक पल की भी देरी नहीं करती हैं और नीतीश कुमार की भविष्य की राजनीति में यही होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। और नीतीश कुमार के पास पश्चाताप और हाथ मलने के सिवा कुछ भी नहीं होगा।

राजनीति और आर्थिक विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान

अर्चना शर्मा

भारत की राजनीति और भारत के आर्थिक विकास में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तरप्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। यह वहीं प्रदेश है जिससे निकल कर की देश की सत्ता तक जाया जा सकता है। वहीं देश के आर्थिक विकास में भी उप्र का योगदान होता है। यह प्रदेश जनसंख्या और क्षेत्रफल की दष्टि से भी काफी बड़ा है। देश का बहुत बड़ा भूभाग इस प्रदेश में समाहित है। हालांकि यह भी सत्य है कि देश के बाकी कुछ राज्यों की तुलना में उप्र का विकास उन राज्यों की तरह नहीं हुआ है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राज्या ने सभी क्षेत्रों में विकास किया है। खासकर जबसे राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तबसे प्रदेश ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति की है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रदेश का मान बढ़ा है। कहा भी जाता है कि भारत की आर्थिक विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से गुजरता है। अगर उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा तो भारत आगे नहीं बढ़ सकता। उत्तर प्रदेश का लगातार तेजी से विकास के रास्ते पर चलना एक उम्मीद जगाता है। राज्य में करोड़ों लोग गरीबी की रेखा से बाहर हुए हैं। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में आज दिन या रात को जाएं तो आपको एक दशक पहले की तुलना में अभूतपूर्व अंतर दिखाई देगा। नोएडा से लेकर आगरा और कानपुर से लेकर बनारस

तक, आपको हर जगह चमचमाते बाजार, मॉल और व्यवसायिक प्रतिष्ठान दिखाई देंगे। यूपी में किसी से भी बात करें, निश्चित रूप से वह अब यही कहता है कि यूपी आगे बढ़ रहा है और कानून-व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। नए उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों और निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। यहां आर्थिक गतिविधियां तीव्र गति से संचालित की जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सही कहते हैं कि उनका राज्य बीमारु श्रेणी से बाहर निकलकर अब सक्षम

भारत को यदि 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है तो इसके लिए बडी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय को बढाना भी अति आवश्यक है।

प्रतिशत), लखीमपुर खीरी (25.33 प्रतिशत), श्रावस्ती (24.42 प्रतिशत), जौनपुर (26.65 प्रतिशत), बस्ती (23.36

किया जाता रहा है। आमतौर पर इसका अर्थ यह होता है कि ये राज्य आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कुपोषण, सड़क, बिजली, पानी समेत अन्य सभी सूचकांकों में पिछड़े हुए हैं। भारत को यदि 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है तो इसके लिए बडी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्तिआय को बढाना भी अति आवश्यक है। यह भी सत्य है कि नए परिसीमन के चलते उत्तर प्रदेश पूर्व के मुकाबले राजनीतिक रूप से आज अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। भारत के आर्थिक

राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उनकी यह टिप्पणी नीति आयोग द्वारा जारी उस रिपोर्ट के बाद आयी, जिसमें कहा गया कि भारत में 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी की रेखा से उपर उठकर बाहर निकले। गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट वाले राज्यों में यूपी शीर्ष पर है। यूपी में गरीबी में सर्वाधिक कमी वाले जिले महराजगंज (29.64 प्रतिशत), गोंडा (29.55 प्रतिशत), बलरामपुर (27.9 प्रतिशत), कौशांबी (25.75

प्रतिशत), गाजीपुर (22.83 प्रतिशत), कुशीनगर (22.28 प्रतिशत) और चित्रकूट (21.40 प्रतिशत) है। जो लोग यूपी को जानते हैं वे आपको बताएंगे कि इन जिलों की हालत पहले बहुत खराब थी। इसलिए यदि राम और कृष्ण की जन्मस्थली यूपी से दिल को छू लेने वाली ऐसी सुखद खबर आ रही है तो यह न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लिए एक शुभ संकेत है। बीमारूशब्द का प्रयोग अक्सर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को संदर्भित करने के लिए

लक्ष्यों की प्राप्ति में बड़ी भूमिका के निर्वाहन में यूपी, समाज के विभिन्न स्तरों के साथ राजनीतिक नेतृत्व के जरिए योगदान दे सकता है। यदि उत्तर प्रदेश नेतृत्व करे तो इसमें कोई शक नहीं कि भारत एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन सकता है। यूपी को आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुसंधान एवं विकास, आईपी और एआई के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन, रक्षा उत्पादों के निर्माण और फार्मास्यूटिकल्स सरीखे उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने दावा किया कि 2015-2016 से 2019-2021 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तरप्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक से पता चला है कि इस अवधि के दौरान 13.5 करोड़ लोगों में से अकेले यूपी में 3.43 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। यह एक चौंका देने वाली संख्या है। 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 707 प्रशासनिक जिलों पर केंद्रित रिपोर्ट उत्तरप्रदेश में सबसे तेज गति से गरीबों की संख्या में कमी का इशारा करती है। गरीबी कम होने के मामले में बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्य यूपी के बाद ही आते हैं। सरकार ने दावा किया है कि रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि राज्य भर के गांवों में गरीबों की संख्या तेजी से घटी है। इतना ही नहीं स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन की गुणवत्ता सरीखे मानकों पर भी बेहतरीन परिणाम दिखे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट पर आगरा के उद्यमी और रोटरी क्लब के प्रमुख मनीष मित्तल कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में उत्साहजनक माहौल है। राज्य सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। मेरा विश्वास करें, हमारा व्यवसाय अच्छा चल रहा है और हम आर्थिक विकास में एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार हैं। काम के इच्छुक लोगों के लिए काम की कोई कमी नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, पोषण से वंचित गरीबों की संख्या 2015-16 में 30.40 प्रतिशत से घटकर 2019-21 में 18.45 प्रतिशत रह गई है। इसमें कहा गया है कि बच्चों और किशोरों की मृत्यु दर में भी सुधार हुआ है, जो 2015-16 में 3.81 प्रतिशत से गिरकर 2019-21 में 2.20 प्रतिशत हो गई है। राज्य में मातृ स्वास्थ्य में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मातृ मृत्यु दर 2015-16 में 25.20 प्रतिशत से घटकर 2019-21में 15.97 प्रतिशत हो गई है। इसके अलावा, खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच नहीं रखने वाले गरीबों का प्रतिशत 2015-16 में 34.24 प्रतिशत के मुकाबले 2019-21 में 17.95 प्रतिशत था। इसके अलावा पीने के पानी से वंचित लोगों की संख्या 2015-16 में 2.09 प्रतिशत के मुकाबले 2019-21 में 0.93 प्रतिशत हो गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि कभी विकास के पैमाने पर पिछडे यूपी में आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चौतरफा विकास हो रहा है। खैर, आज दुनिया भी यह मानने लगी है कि उत्तर प्रदेश अब गरीब और बीमारू राज्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा राज्य है जहां पिछले छह वर्षों में 5.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उपर उठे हैं। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यह दुख की बात है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस, सपा और बसपा की सरकारें गरीबी तो दूर कर नहीं पाई, लेकिन खोखला नारा जरूर देकर गईं। सपा के नारे जातिवाद और अराजकता के चंगुल में फंसकर भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए जबकि बसपा शासन में यूपी विकास की दौड़ में अन्य राज्यों से काफी पीछे रह गया। उत्तरप्रदेश में पिछले छह वर्षों में जो विकास और जनकल्याण के कार्य दिखे हैं, वे पहले भी हो सकते थे। लेकिन, पिछली सरकारों में इच्छाशक्ति का अभाव स्पष्ट दिख रहा था। उन्होंने किसानों और व्यापारियों का भरपूर शोषण किया, युवाओं के साथ अन्याय भी किया और महिलाओं की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाला। जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांच सालों में 01 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य बनाया है। यह राज्य समेत यहां के निवासियों की क्षमताओं को बेहतर संभावनाओं में बदलने का एक सुअवसर है। भारत समेत दुनिया भर में गरीबी कम करने, जीवन स्तर में सुधार के लिए सबसे शक्तिशाली और टिकाउ यदि कोई रास्ता है तो वो आर्थिक विकास ही है, और मिशन 01 ट्रिलियन में यूपी को बदलने की क्षमता है। उत्तरप्रदेश में सबसे अच्छी बात यह है कि अब यूपी सामाजिक रूप से बेहतर हो गया है। भय, अत्याचार और गुण्डागर्दी से निजात पाने में सफल हो गया है।

मणिपुर: हिंसा थमी जरूर है लेकिन संकेत शुभ नहीं हैं

मणिपुर में बीते कुछ समय से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच एक भीषण हिंसक संघर्ष चल रहा है। यहां से दो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का एक वीडियो हमारे सामने आया, जिसने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया। इस वीडियो ने हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी व्यथित कर दिया और उन्होंने इस घटना को 140 करोड़ भारतवासियों को शर्मसार करने वाला बताया। साथ ही, यह भी आश्वस्त किया कि इस घटना के आरोपियों को किसी भी सूरत में बख़्शा नहीं जाएगा।

अमित राय

मणिपुर में बीते कुछ समय से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच एक भीषण हिंसक संघर्ष चल रहा है। यहां से दो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का एक वीडियो हमारे सामने आया, जिसने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया। इस वीडियो ने हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी व्यथित कर दिया और उन्होंने इस घटना को 140 करोड़ भारतवासियों को शर्मसार करने वाला बताया। साथ ही, यह भी आश्वस्त किया कि इस घटना के आरोपियों को किसी भी सूरत में बख़्शा नहीं जाएगा। आज यह एक जगजाहिर तथ्य है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में मणिपुर, असम से लेकर त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों ने विकास, शांति और समृद्धि के नये आयामों को हासिल किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्द्रीय सत्ता में आते ही एक्ट ईस्ट नीति को हमारे सामने लाया, जिसके माध्यम से उनका प्रयास भारत-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ बेहतर राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को विकसित करना है। उनके इस प्रयास से

कभी शेष भारत से बिल्कुल कटा हुआ महसूस करने वाले पूर्वोत्तर के राज्य आज हमारे विकास के प्रवेश द्वार और अष्ट लक्ष्मी के रूप में अपनी एक विशेष पहचान स्थापित कर चुके हैं। मणिपुर में दो समुदायों के बीच जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है लेकिन, मणिपुर हिंसा जैसी घटनाओं से पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास को लेकर हो रहे सभी प्रयासों पर निश्चित रूप से बेहद नकारात्मक असर पड़ेगा और ऐसी घटनाएं दोबारा न हो हमें यह सुनिश्चित करना होगा। हालांकि, इतने संवेदनशील मुद्दे को लेकर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने जिस प्रकार का रवैया दिखाया है। वह वास्तव में बेहद दु:खद और खतरनाक है। उन्हें यह समझना होगा कि यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस पर किसी प्रकार की राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए।

मणिपुर हिंसा जैसी घटनाओं से पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास को लेकर हो रहे सभी प्रयासों पर निश्चित रूप से बेहद नकारात्मक असर पड़ेगा और ऐसी घटनाएं दोबारा न हो हमें यह सुनिश्चित करना होगा।

विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं, कि उन्होंने आखिर ढाई महीने से चल रहे मणिपुर हिंसा को लेकर कुछ कहा क्यों नहीं? वे क्षेत्र का दौरा करने क्यों नहीं गये? विपक्ष के ये सवाल वास्तव में उनकी अज्ञानता और राष्ट्र के प्रति उनकी अनिष्ठा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और उनके दिशानिर्देशों पर शांति स्थापित करने के तमाम प्रयास किये जा रहे हैं। और, सवाल जहां तक प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी का है, तो आलोचक जरा स्वयं सोचें कि ऐसे समय में, जब भारत जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है और हमारे सामने कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान से भारत को लेकर दुनिया में क्या संदेश जाएगा? विपक्ष को यह यथाशीघ्र समझने की आवश्यकता है कि यह पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है और इससे निपटने में हम सक्षम हैं। उन्हें दुनिया के सामने अपने ही देश को छोटा दिखाने का प्रयास बंद कर देना चाहिए। वे मणिपुर हिंसा में विदेशी शक्तियों की संलिप्तता को भी नकार नहीं सकते हैं। यह कोई छिपाने वाली बात नहीं है कि हमारा पड़ोसी देश चीन वर्षों से भारत में विद्रोही संगठनों की मदद कर रहा है और पूर्वोत्तर के राज्यों में बीते कुछ वर्षों में जिस प्रकार से मादक पदार्थों की

बरामदगी की गई है। वह चिन्ता का एक प्रमुख विषय है। ऐसे में विपक्ष को किसी भी मुद्दे को तूल देने से पहले, अपने राष्ट्रीय सरोकारों के विषय में विचार करना आवश्यक है। ख़ैर, अब मणिपुर में स्थिति सामान्य हो रही है। यहां हाल के कुछ दिनों में हिंसा के कारण न किसी की मौत हुई है और न ही अब विद्याल या सरकारी कार्यालय बंद हैं। इस घटना को लेकर केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में भी अपना हलफ़नामा दायर किया है। इस हलफ़नामे के अनुसार, मणिपुर राज्य सरकार द्वारा इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने के बाद आगे की कार्रवाई बेहद तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं, मामले की त्वरित जांच के लिए केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से यह आग्रह किया है कि इसे मणिपुर से 'बाहर किसी भी अन्य राज्य में' स्थानांरित कर दिया जाए। इस हिंसा को लेकर अब तक लगभग 14 हजार लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और राज्य के सुरक्षा व्यवस्था को चौकस करने, मध्यस्थता और राजनीतिक बीच-बचाव के मामले में केन्द्र सरकार अपनी भूमिकाओं को भली-भांति निभा रही है।

गौरतलब है कि मणिपुर में अभी तक राज्य पुलिस के अलावा, केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों की 124 अतिरिक्त कंपनियां और आर्मी/असम राइफल्स की 185 टुकड़ियां भी तैनात हैं। यहां सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह की अगुवाई में अलग-अलग सुरक्षा बलों के एक एकीकृत कमांड का गठन किया गया है। वहीं, अब मणिपुर सरकार ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर राज्य में म्यांमार से आए लोगों का बायोमीट्रिक डेटा लेना फिर शुरूकर दिया है। इसका उद्देश्य मणिपुर में अवैध रूप से रह रहे म्यांमार के नागरिकों की पहचान करना है। बहरहाल, यदि हम बीते 9 वर्षों के आंकड़े को देखें तो पूर्वोत्तर भारत में राह भटके 8 हजार से भी अधिक युवाओं ने आत्मसमर्पण किया है। इस वजह से यहां उग्रवाद संबंधित घटनाओं में 76 प्रतिशत से भी अधिक की कमी आई है। ये परिणाम निश्चित रूप से, मोदी-शाह की अगुवाई में एनएलएफटी समझौता-2019 व बोड़ो समझौता-2020, कार्बी समझौता-2021 और 2022 के भारत सरकार, असम सरकार और बीसीएफ, एसीएमए, एएएनएलए, एपीए, एसटीएफ, एएएनएलए (एफजी), बीसीएफ (बीटी), एसीएमए (एफजी) जैसे आठ आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों के बीच हुए ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौतों से आए हैं। ऐसे में, मणिपुर में आज भले ही परिस्थितियां प्रतिकूल हों। लेकिन हमें बिना परेशान हुए। बिना व्यथित हुए। प्रधानमंत्री मोदी पर अपने विश्वास को कायम रखना होगा। वे अवश्य इस मुश्किल समस्या का कोई न कोई स्थायी समाधान ढूंढ लेंगे।

वीरांगना रानी दुर्गावती

मातृभूमि की रक्षा में प्राणों का बलिदान करके अपने लहू से इतिहास के पृष्ठों पर शौर्य एवं वीरता की प्रेरक और रोमांचक गाथा अंकित करने वाली वीरांगना रानी दुर्गावती इतिहास में अमर हैं। सोलहवीं शताब्दी में गोंडवाना और गढ़ा-मण्डला की महारानी दुर्गावती ने मुगल सम्राट अकबर की आक्रान्ता सेनाओं से अपनी मातृभूमि की रक्षा करने लोहा लिया और जबलपुर के निकट नर्रई नाला के पास वीरगति पाई।

रानी के बलिदान को 459 वर्ष हो जाने के बाद भी लोग उनके शौर्य, अप्रतिम देशप्रेम, साहस, शासन नैपुण्य, प्रजा वात्सल्यता और प्राणोत्सर्ग को याद करते हैं। चार शताब्दियों से अधिक समय बीतने के बाद भी दुर्गावती की कीर्ति, बलिदान गाथा और वीरता की कहानी अक्षुण्ण बनी हुई है। रानी दुर्गावती के प्रारंभिक जीवन के संबंध में अबुल फज़ल ने आइने अकबरी में लिखा है कि राजकुमारी दुर्गावती महोबा के पास राव परगने के चंदेल वंशीय शासक शालिवाहन की पुत्री थी। अंग्रेज इतिहासकार कनिंघम के अनुसार दुर्गावती कालिंजर के राजा कीरतसिंह की पुत्री थी। उनका जन्म सन 1524 में हुआ। रानी दुर्गावती का विवाह गढ़ा-मंडला के तेजस्वी सम्राट संग्रामशाह के ज्येष्ठ पुत्र दलपतिशाह के साथ हुआ था। उन्होंने अनेक मंदिर, मठों, धार्मिक प्रतिष्ठानों सहित प्रजाहित में जलाशयों का निर्माण, धर्मशाला और संस्कृत पाठशालाओं की व्यवस्था की।

दुर्गावती के शासन में नारी सम्मान अपनी उत्कर्ष अवस्था पर था। नारी के अपमान पर मृत्युदंड दिया जाता था। रानी नित्य नर्मदा स्नान करती थी और इसके लिए राज प्रसादों से नर्मदा तट तक कई गुप्त और अभेद्य मार्ग बनवाये गये थे। राज्य में संस्कृत पंडितों और कवियों को राज्य सम्मान प्राप्त था। रानी को विद्या, ज्ञानार्जन और साहित्य के प्रति अत्यधिक रु चि थी। दुर्गावती का राज्य छोटे-बड़े 52 गढ़ों से मिलकर बना था, जिसमें सिवनी, पन्ना, छिंदवाड़ा, भोपाल, तत्कालीन होशंगाबाद और अब नर्मदापुरम, बिलासपुर, डिंडौरी, मंडला, नरसिंहपुर, कटनी तथा नागपुर शामिल थे। मोटे तौर पर राज्य विस्तार उत्तर से दक्षिण 300 मील एवं पूर्व से पश्चिम 225 मील कुल 67 हजार 500 वर्ग मील के क्षेत्र में था।

रानी दुर्गावती ने सन् 1549 से 1564 तक अपने पुत्र वीरनारायण सिंह के नाम पर गोंडवाना साम्राज्य की बागडोर सम्भाली। राज्य की सुरक्षा के लिये किले बनवाये और किलों की मरम्मत की। शहर और गाँव

बसाये और कृषि प्रधान 23 हजार गाँवों की देख-रेख की। आइने अकबरी में लिखा है कि गढ़ा-मण्डला की आमदनी 18 लाख 57 हजार दीनार थी। दुर्गावती के राज्य में सोने के सिक्के चलते थे। राज्य में इतनी समृद्धि थी कि कहा जाता है कि लोग अपनी जमीन का लगान स्वर्ण मुद्राओं से चुकाते थे। राज्य के 12 हजार गाँवों में रानी के प्रतिनिधि शिकदार रहते थे। प्रजा की फरियाद रानी स्वयं सुनती थी।

रानी ने कभी दूसरों के राज्यों पर न तो आक्रमण किया और न साम्राज्यवादी तरीकों की विस्तारवादी नीति अपनाई। गोंडवाने पर मालवा के बाजबहादुर ने आक्रमण किया। पहली बार के संघर्ष में बाजबहादुर का काका फतेह खाँ मारा गया और दूसरी बार कटंगी की घाटी में बाजबहादुर की सारी फौज का सफाया हुआ। बाजबहादुर की पराजय ने रानी दुर्गावती को गढ़ा मण्डला का अपराजेय शासक बना दिया। गढ़ा-मण्डला की समृद्धि से प्रभावित आसफ खाँ के नेतृत्व में दस हजार घुड़सवार और तोपों, गोला-बारूद से लैस मुगल सैनिकों ने दमोह की ओर से गोंडवाना राज्य पर हमला कर दिया। मंत्रियों ने रानी को पीछे हटने एवं संधि करने की सलाह दी। लेकिन स्वाभिमानी दुर्गावती ने अकबर के सेनापति से बात करना मुनासिब नहीं समझा। जब मुगल सेना का तोपखाना जबलपुर के बारहा ग्राम के पास नरई नाला के निकट पहुँचा तो रानी ने कूटनीति का परिचय देते हुए मंत्रियों से कहा कि रात्रि में ही मुगल सेना पर आक्रमण करना उचित होगा। रानी के सलाहकारों ने रानी की रणनीति का समर्थन नहीं किया। विषम परिस्थितियों में रानी स्वयं सैनिक वेश में अपने प्रिय हाथी सरमन पर सवार होकर दो हजार पैदल सैनिकों की टुकड़ी के साथ निकल पड़ी। रानी और उनका किशोर पुत्र असाधारण वीरता के साथ मुगल सेना पर टूट पड़े। इसी बीच रानी की कनपटी एवं आँख के पास तीर लगने से रानी घायल हो गई। उन्हें लगा कि मुगलों की इस सेना को इस अवस्था में पराजित करना संभव नहीं है तो उन्होंने युद्ध स्थल में स्वयं की छाती पर कटार घोप कर 24 जून 1564 को प्राणोत्सर्ग कर दिया।

वीरांगना दुर्गावती की शासन व्यवस्था, रण-कौशल और शौर्य की अलग-अलग कालखंडों के इतिहासकारों ने अपने-अपने नजरिये से समीक्षा की है। संस्कृत में राजकवियों ने उन पर प्रशस्तियां लिखी है। श्री गोविन्द विश्वास भावे ने रानी दुर्गावती के संपूर्ण जीवन और चरित्र पर अंग्रेजी में एक विशद लेख लिखा है जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक फाइव फेमस वुमेन ऑफ इंडियन हिस्ट्री में है। उपन्यासकार श्री वृंदावनलाल वर्मा के अनुसार रानी जैसे व्यक्तित्व को अवतार की कोटि में रखा जा सकता है। आइने अकबरी के लेखक अबुल फजल ने लिखा है कि रानी ने महान कार्य करते हुए अपनी दूरदर्शिता और योग्यता से राज्य किया। उसने मांडू के शासक को हराया। रानी के पास बड़ी संख्या में घुड़सवार और एक हजार प्रसिद्ध हाथी थे। वे 'भाला और बंदूक दोनों में ही दक्ष थीं।' प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेन्ट स्मिथ लिखते हैं कि 'उत्तम चरित्र वाली रानी पर अकबर का आक्रमण एक अन्यायपूर्ण अत्याचार कहा जायेगा।' फारसी इतिहासकार फरिश्ता ने भी रानी का यशोगान किया और कहा कि 'उनका अंत भी उतना महान और उच्च था जितना उनका जीवन।' आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने ब्रज भाषा में दुर्गावती की यश गाथा लिखी है।

सहायक सूचना अधिकारी, जनसम्पर्क

डेढ़ दशक में जन-सहयोग से विकसित राज्य के रूप में उभरा मध्यप्रदेश

देश के हृदय स्थल मध्यप्रदेश ने पिछले डेढ़ दशक में विकास के नये आयाम स्थापित कर विकसित राज्य की पहचान बना ली है। मध्यप्रदेश की सुशासन और विकास रिपोर्ट-2022 के अनुसार राज्य में आए बदलाव से मध्यप्रदेश बीमारू से विकसित प्रदेशों की पंक्ति में उदाहरण बन कर खड़ा हुआ है। इस महती उपलब्धि में प्रदेश में जन-भागीदारी से विकास के मॉडल ने अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में केन्द्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने मध्यप्रदेश को अन्य राज्यों के लिये अनुकरणीय बना दिया है। इस अरसे में सड़क, बिजली, पानी, कृषि, पर्यटन, जल-संवर्धन, सिंचाई, निवेश, स्व-रोजगार और अधो-संरचना विकास के साथ उन सभी पहलुओं पर सुविचारित एवं सर्वांगीण विकास की नवीन गाथा लिखी गई जो जन-कल्याण के साथ विकास के लिये जरूरी हैं।

बेहतर वित्तीय प्रबंधन और चौतरफा विकास से आज प्रदेश की विकास दर 19.7 प्रतिशत है, जो देश में सर्वाधिक है। देश की अर्थ-व्यवस्था में मध्यप्रदेश 4.6 प्रतिशत का योगदान दे रहा है।

बेहतर वित्तीय प्रबंधन और चौतरफा विकास से आज प्रदेश की विकास दर 19.7 प्रतिशत है, जो देश में सर्वाधिक है। देश की अर्थ-व्यवस्था में मध्यप्रदेश 4.6 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में बीते दशक में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर निरंतर बढ़ रही है। वर्ष 2001-02 में 4.43 प्रतिशत की दर आज बढ़ कर 16.43

प्रतिशत हो गई है प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 71 हजार 594 करोड़ रूपये से बढ़कर 13 लाख 22 हजार 821 रूपये हो गया है। वर्ष 2001-02 में प्रति व्यक्ति आय 11 हजार 718 रूपये थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़ कर एक लाख 40 हजार 583 रूपये हो गई है। राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर विगत एक दशक में राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि दर से अधिक रही है।

विकास प्रक्रिया में अधो-संरचना के महत्व के मद्देनजर मध्यप्रदेश में निरंतर अधो-संरचना विकास हो रहा है। अधो-संरचना बजट जो वर्ष 2002-03 में 3873 करोड़ रूपए था, वह वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 56 हजार 256 करोड़ रुपए हो गया है।

एक समय था जब बिजली आती कम थी और जाती ज्यादा थी। आज प्रदेश बिजली क्षेत्र में आत्म-निर्भर है और 24 घंटे बिजली की उपलब्धता है। वर्ष 2003 में उर्जा क्षमता 5173 मेगावाट थी, जो बढ़ कर 28 हजार मेगावाट हो गई है।

विकास प्रक्रिया में अधो-संरचना के महत्व के मद्देनजर मध्यप्रदेश में निरंतर अधो-संरचना विकास हो रहा है। अधो-संरचना बजट जो वर्ष 2002-03 में 3873 करोड़ रुपए था, वह वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 56 हजार 256 करोड़ रुपए हो गया है।

नवीकरणीय उर्जा के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश अग्रणी है। ओंकारेश्वर में लगभग 3500 करोड़ के निवेश से 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर सोलर पॉवर प्लांट का कार्य प्रारंभ हो गया है। किसानों के खेतों में 50 हजार सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य है। विश्वधरोहर साँची बहुत जल्द सोलर सिटी के रूप में विकसित होकर देश में अपनी अलग पहचान बनायेगा।

अच्छी सड़कें विकास की धुरी होती है। एक समय था, तब यह पता ही नहीं चलता था कि सड़क में गड्डे हैं या गड्डे में सड़क है। अब गाँव-गाँव, शहर-शहर अच्छी गुणवत्तायुक्त सड़कों का जाल बिछाया गया

हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2001-02 में 44 हजार किलोमीटर सड़कें थी, अब 4 लाख 10 हजार किलोमीटर सड़कें बन गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में लगभग 1500 किलोमीटर लंबाई के 40 हजार करोड़ की लागत के 35 कार्य स्वीकृत हैं। अटल, नर्मदा और विंध्य प्रगति पथ के साथ मालवा, बुंदेलखंड और मध्य विकास पथ निर्मित किए जा रहे हैं।

प्रदेश में सभी रेलवे क्रॉसिंग समाप्त करने के लिए 105 रेलवे ओवर ब्रिज के साथ 334 पुलों का निर्माण हो रहा है। साथ ही 86 हजार करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं के कार्य चल रहे हैं। वर्ष 2009 से 2014 के बीच जहाँ प्रदेश को औसतन 632 करोड़ रूपए का रेलवे बजट

प्रदेश में कृषि को लाभ का धंधा बनाना के लिए सिंचाई क्षमताओं का निरंतर विकास किया जा रहा है। वर्ष 2003 में सिंचाई क्षमता केवल 7 लाख 68 हजार हेक्टेयर थी, जो वर्ष 2022 में बढ़ कर 45 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है।

मिलता था, वहीं वर्ष 2022-23 में 13 हजार 607 करोड़ का रेलवे बजट प्रावधान मिला है, जो इक्कीस गुना अधिक है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशन विश्वस्तरीय बनाए जाएंगे। अत्याधुनिक रानी कमलापति स्टेशन देश में एक मॉडल बना है। एक वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ हो चुकी है और आज प्रधानमंत्री श्री मोदी मध्यप्रदेश को 2 और वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने वाले हैं। प्रदेश में हवाई सेवाओं का विस्तार भी निरंतर हो रहा है।

प्रदेश में कृषि को लाभ का धंधा बनाना के लिए सिंचाई क्षमताओं का निरंतर विकास किया जा रहा है। वर्ष 2003 में सिंचाई क्षमता केवल 7 लाख 68 हजार हेक्टेयर थी, जो वर्ष 2022 में बढ़ कर 45 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है। वर्ष 2025 तक सिंचाई क्षमता को बढ़ा कर 65 लाख हेक्टेयर किये जाने पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। हर घर जल से नल योजना पर तेज गति से कार्य हो रहा है, अभी तक लगभग 50 प्रतिशत घरों तक नल से जल पहुँच चुका है। आजादी के अमृत काल

में प्रदेश में अब तक 5936 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण किया जा चुका है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम चरण में बांध, लिंक नहर तथा पॉवर हाउस का निर्माण कार्य इस वर्ष प्रारंभ होगा। अटल भू-जल योजना में भी लगभग 700 ग्राम पंचायतों में वॉटर सिक्युरिटी प्लान बनाए गए हैं।

अधो-संरचना विकास और बेहतर वित्त प्रबंधन के साथ कृषि प्रधान होने की वजह से प्रदेश में तेज गति से कृषि विकास और किसान-कल्याण के कार्य भी किए जा रहे हैं। लगातार 7 बार प्रतिष्ठित कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त करने वाले मध्यप्रदेश ने गेहूँ उपार्जन में पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश का सोने जैसे दानों वाला गेहूँ अमेरिका सहित अनेक देशों में निर्यात होता है। अब इसके निर्यात के लिए प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। प्रदेश में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी बनाई गई है। कृषि विकास दर जो वर्ष 2002-03 में 03 प्रतिशत थी, वह वर्ष 2020-21 में बढ़ कर 18.89 प्रतिशत हो गई है। खेती और एलाइड सेक्टर का बजट भी 600 करोड़ से बढ़कर 53 हजार 964 करोड़ हो गया। खाद्य उत्पादन भी इस अवधि में 159 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 619 लाख मीट्रिक टन हो गया है।

उद्यानिकी फसलों का रकबा 4 लाख 67 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 25 लाख हेक्टेयर हो गया है। फसल उत्पादन 224 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 725 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। फ़सल उत्पादकता 1195 किलोग्राम से बढ़ कर 2421 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। किसान-कल्याण के ध्येय से प्रदेश में गत 3 वर्षों में फ़सलों की नुकसानी पर 4000 करोड़ से अधिक की राहत राशि वितरित की गई है। प्रदेश के 11 लाख से अधिक डिफाल्टर किसानों का 2123 करोड़ का ब्याज माफ करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना प्रारंभ की गई है। पिछले 3 वर्षों में किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं में 2 लाख 69 हजार 686 करोड़ रुपये से अधिक के हितलाभ वितरण किए गए हैं। फ़सल क्षति प्रतिपूर्ति दरों में भी कई गुना वृद्धि की गई है।

अधो-संरचना, खेती-किसानी तथा किसान-कल्याण के क्षेत्र में प्रदेश की प्रगति और विकास की यह कहानी तो एक बानगी है। प्रदेश में पिछला डेढ़ दशक हर क्षेत्र में प्रगति, विकास और लोगों की तरक्की-खुशहाली का गवाह है।

जनसंपर्क फीचर

मध्यप्रदेश में कृषि और खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में मौजूद अपार संभावनाएँ

क्रांतिदीप अलूने

निरंतर बढ़ती आबादी के पोषण के लिए उसी अनुपात में फ़सलों का उत्पादन, कृषि गतिविधियों और खाद्य व्यापार में वृद्धि जरूरी हो जाती है। दुनिया में आबादी लगातार बढ़ रही है और वर्ष 2050 तक इसके 10 अरब तक पहुँचने का अनुमान है। वैश्विक कृषि बाजार वर्ष 2022 में 11 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ कर 12.1 ट्रिलियन डॉलर हो गया हैं जो वर्ष 2026 तक 16.67 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच जाने की उम्मीद है। देश के दिल में बसा मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। इसकी जीएसडीपी में कृषि का योगदान 47 फीसदी है। इसीलिए मध्यप्रदेश को फूड बास्केट ऑफ इंडिया कहलाने का गौरव मिला हैं। प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। इसी के मद्देनज़र प्रदेश में कृषि और खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में अपार संभावनाएँ मौजूद हैं।

> **देश के दिल में बसा मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। इसकी जीएसडीपी में कृषि का योगदान 47 फीसदी है। इसीलिए मध्यप्रदेश को फूड बास्केट ऑफ इंडिया कहलाने का गौरव मिला हैं।**

मध्यप्रदेश देश में संतरा, मसाले, लहसुन, अदरक, चना और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज्य में जैविक उत्पादों की खेती का रकबा भी अच्छा खासा है। सोयाबीन, गेहूँ, मक्का, खट्टे फल, प्याज और फूलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तिलहन, बागवानी, मिर्च, सुगंधित, औषधीय पौधों और दुग्ध का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 'शरबती गेहूँ' का सर्वाधिक उत्पादक और निर्यातक है। शरबती गेहूँ का आटा देश में उच्चतम गुणवत्ता वाला माना गया है।

राज्य का कृषि-जलवायु क्षेत्र 11 भाग में विभक्तहै। इससे कृषि उपज में विविधता दिखायी देती है। प्रदेश में 10 प्रमुख नदी घाटियाँ और 0.3 मिलियन हेक्टेयर में फैले अंतर्देशीय जल निकाय, 17 हजार किलोमीटर से अधिक फैली हुई नदियाँ और नहरें, 60 हजार हेक्टेयर से अधिक छोटे-बड़े तालाबों से पानी की भरपूर उपलब्धता से राज्य में कृषि उत्पादन को और ज्यादा बढ़ावा मिला है।

मध्यप्रदेश में बेहतर बीज गुणवत्ता के विकास, उर्वरकों, चारा उत्पादन और आपूर्ति, कृषि मशीनरी और उपकरणों के निर्माण और सिंचाई परियोजनाओं में पूँजी निवेश पर विशेष ध्यान देने के साथ ही खेती के क्षेत्र में निवेश के लिए बहुत सारे मौके हैं। साथ ही कृषि और खाद्य प्र-संस्करण मूल्य श्रंखला में मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य आर्टिफीशयल इंटेलिजेंस (एआई), ब्लॉकचेन और संबंधित डिजिटल सेवाओं को भी प्रदेश में प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश में बेहतर बीज गुणवत्ता के विकास, उर्वरकों, चारा उत्पादन और आपूर्ति, कृषि मशीनरी और उपकरणों के निर्माण और सिंचाई परियोजनाओं में पूँजी निवेश पर विशेष ध्यान देने के साथ ही खेती के क्षेत्र में निवेश के लिए बहुत सारे मौके हैं।

खाद्य प्र-संस्करण

मध्यप्रदेश सरकार ने मेगा फूड पार्क, कृषि प्र-संस्करण क्लस्टर, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवद्धित अवसंरचना, खाद्य प्र-संस्करण और संरक्षण क्षमताओं को बढ़ाने की पहल की है। कृषि, खाद्य और डेयरी प्र-संस्करण क्षेत्र कोबढ़ाने के लिये भी कई कार्य किये जा रहे हैं। सूक्ष्म खाद्य प्र-संस्करण के पीएम फॉर्माइजेशन की केन्द्र सरकार की पहल, राज्य उद्यमियों की क्षमता निर्माण और किसान उत्पादक संगठनों, स्व-सहायता समूहों को सहायता देने, असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्र-संस्करण उद्यमों की चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। उत्पादक सहकारी समितियाँ और सहकारी समितियाँ अपनी संपूर्ण मूल्य श्रंखला के साथ सूक्ष्म उद्यमों को सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाती हैं।

वर्ष 2021 में दुनिया के खाद्य प्र-संस्करण बाजार का आकार 5.7 ट्रिलियन था। इस क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 7.60 प्रतिशत की कम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट (सीएजीआर) से बढ़ने का अनुमान है, जिसमें एशिया प्रशांत इस क्षेत्र का प्रमुख क्षेत्र है। भारत, इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया जैसे उभरते बाजार तेजी से वैश्विक विकास

को गति देंगे। बढ़ते ग्राहक आधार के करीब होने के लिए विनिर्माण और प्र-संस्करण तेजी से इन बाजारों में जायेंगे। भारत का खाद्य उत्पादन उद्योग 400 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का है और इसके बढ़ने की उम्मीद है। यह वर्ष 2025-26 तक 535 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुँचेगा। भारत की विश्व स्तर पर खाद्य उत्पादन में एक मजबूत स्थिति है और इसे कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उत्पादों के चीन के बाद दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में स्थान दिया गया है।

इस परिदृश्य में मध्यप्रदेश, खाद्य प्र-संस्करण उद्योग को सशक्तबनाने के लिये लगातार काम कर रहा है। राज्य में 8 स्थान पर सरकारी वित्त-पोषित फूड पार्कों की स्थापना, 2 निजी मेगा फूड पार्क और एपीसी के तहत अनुमोदित 4 कृषि प्र-संस्करण क्लस्टर जैसी कई पहल की गई है। राज्य ने अपनी भण्डारण क्षमता को लगभग 15 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया है और यहाँ 3 लाख 54 हजार वर्गमीटर की कुल सीमा के साथ एक

> **खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र के अलावा, डेयरी गतिविधियाँ मध्यप्रदेश की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो रोजगार और आय का महत्वपूर्ण साधन भी है। ज्यादातर डेयरी उत्पाद दूध के रूप में बेचे जाते हैं। इसलिये इस क्षेत्र में मूल्यवर्धन और समग्र डेयरी प्र-संस्करण की जबरदस्त संभावनाएँ मौजूद हैं।**

विशाल कोल्ड-स्टोरेज हैंडलिंग क्षेत्र है।

खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में प्रतिभाओं को निखारने के लिये मध्यप्रदेश सरकार ने फूड इनोवेशन हब विकसित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ सहयोग किया है। राज्य में पहले से ही 5 प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जो इस क्षेत्र के लिए मूल्य श्रृंखला में मौजूदा कार्य बल को शिक्षित करने और प्रतिभाशाली कौशल बल जोड़ने के लिए समर्पित हैं। मध्यप्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार के प्रोत्साहनों के ईतर भी प्रोत्साहनों से उद्योगों को आकर्षित कर रही है।

मध्यप्रदेश ने हाल के दिनों में कैडबरी, आईटीसी, यूनिलीवर जैसी दिग्गज नामी कम्पनियों को शासन स्तर से अनुकूल नीतिगत बेहतर वातावरण उपलब्ध करा कर निवेश को आकर्षित किया है। मध्यप्रदेश सरकार ने खाद्य प्र-संस्करण उद्योग समर्थक नीतियाँ बनायी हैं। वित्तीय मोर्चे पर, खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र को दिया जाने वाला प्रोत्साहन राज्य के अन्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन का डेढ़ गुना है। राज्य ने अपने निर्यात को वर्ष 2005-06 में 83 करोड़ रुपये मूल्य के 9 हजार 600 मीट्रिक टन से बढ़ा कर वर्ष 2021-22 में एक हजार 300 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग एक लाख 43 हजार मीट्रिक टन कृषि उत्पादों को 18 प्रतिशत से अधिक के आश्चर्यजनक सीएजीआर के साथ बढ़ाया है।

एक जिला-एक उत्पाद योजना में मध्यप्रदेश ने 24 कृषि और बागवानी से संबंधित प्राथमिक उत्पादों की पहचान की है। कोदो-कुटकी, बाजरा, संतरा/साइट्रस, सीताफल, आम, टमाटर, अमरूद, केला, पान, आलू, प्याज, हरी मटर, मिर्च, लहसुन, अदरक, धनिया, सरसों के उत्पाद, गन्ना उत्पाद, आँवला और हल्दी इसमें शामिल हैं। संतरे का उत्पादन प्रदेश को संतरा प्र-संस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए आदर्श बनाता है। प्रदेश में बैतूल, कटनी, अनूपपुर, रीवा, सिंगरौली और रायसेन जिले में आम आधारित कई खाद्य प्र-संस्करण उद्योग स्थापित होने के विभिन्न चरण में हैं।

राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों की जलवायु और क्षमताओं के आधार पर किसानों को ऐसी उपज लगाने के लिये प्रोत्साहित किया है जिससे रस, जैम, स्क्वैश, सिरप, सौंदर्य उत्पाद, इत्र, आवश्यक तेल, लुगदी, सूखे आम पाउडर, चटनी, आम जैसे प्र-संस्कृत खाद्य उत्पादों का उत्पादन किया जा सकता है।

खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र के अलावा, डेयरी गतिविधियाँ मध्यप्रदेश की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो रोजगार और आय का महत्वपूर्ण साधन भी है। ज्यादातर डेयरी उत्पाद दूध के रूप में बेचे जाते हैं। इसलिये इस क्षेत्र में मूल्यवर्धन और समग्र डेयरी प्र-संस्करण की जबरदस्त संभावनाएँ मौजूद हैं। वर्तमान में तरल दूध का हिस्सा राज्य के कुल बाजार हिस्सेदारी का 48 प्रतिशत है। सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में दही, पनीर, यूएचटी दूध, फ्लेवर्ड दूध और छाछ शामिल हैं।

मध्यप्रदेश तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है। दुग्ध उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। देश के कुल दुग्ध उत्पादन में प्रदेश का 8.6 प्रतिशत का योगदान है। मध्यप्रदेश सहकारी डेयरी फेडरेशन- शीर्ष निकाय एमपीसीडीएफ की अकेले 9 लाख 13 हजार केजीपीडी की औसत दूध खरीद दर्ज की गई है। डेयरी प्र-संस्करण में शामिल प्रमुख कंपनी-उपक्रमों में अमूल साँची, अनित इंडस्ट्रीज सौरभ और पवनश्री फूड इंटरनेशनल शामिल हैं। कुल मिलाकर राज्य में समग्र कृषि, खाद्य और डेयरी प्र-संस्करण मूल्य श्रृंखला में निवेश के भरपूर अवसर है।

नीति आयोग या अनीति आयोग?

रघु ठाकुर

भारत के नीति आयोग ने मल्टी डाइमेन्शन पावर्टी इन्डेक्स 2023 जारी किया है। जिसमें बताया गया है कि पिछले चार वर्ष में 11.50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं और अब देश कि मात्र 15 प्रतिशत आबादी ही गरीबी रेखा के नीचे है। नीति आयोग ने यह भी बताया है कि मध्यप्रदेश, राजस्थान और बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी घटी है और शहरों में तो अब मात्र 5 प्रतिशत आबादी ही निर्धन बची है। नीति आयोग की रपट का विश्लेषण भी जरूरी है और वर्तमान में घट रही घटनाओं के परिपेक्ष्य में इन आंकड़ों को विश्लेषित करना भी आवश्यक है। मैं मानता हूं कि नीति आयोग की सरकार के प्रति निष्ठा और लाचारी स्वाभाविक है। क्योंकि नीति आयोग का गठन भी भारत सरकार ने किया है। इसी रपट में नीति आयोग ने बताया है कि, देश के तेरह राज्यों में 50 प्रतिशत परिवारों में गैस सिलेंडर नहीं है। इनमें से 43 प्रतिशत परिवार हरियाणा और 25 प्रतिशत परिवार पंजाब प्रांत के हैं। यह एक स्थापित तथ्य है कि देश में सर्वाधिक सिचिंत क्षेत्र या कहे कि लगभग शत-प्रतिशत सिचिंत क्षेत्र हरियाणा और पंजाब में है। इसके अलावा पंजाब में लघु और स्थानीय उद्योगों का भी एक व्यापक योगदान है। पंजाब की एक बड़ी आबादी अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और कनाडा आदि देशों में जाकर काम कर रही है और काफी मात्रा में विदेशी पैसा भी वहां इस कारण आता है। इसके बावजूद भी अगर पंजाब में 25 प्रतिशत और हरियाणा में 43 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं कि जो गैस सिलेंडर नहीं खरीद सकते तथा लकड़ी कोयला आदि पर किसी प्रकार अपना जीवन निर्वाह कर रहें हैं तो फिर नीति आयोग के आंकड़ों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अगर शहरों में मात्र 5 प्रतिशत आबादी निर्धन है तो फिर

शहरों की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी मुफ्त का राशन, मुफ्त की बिजली-पानी लेने को बाध्य क्यों हैं? पंजाब और हरियाणा तो छोड़ो देश की राजधानी दिल्ली की हालत यह है कि सरकारी राशन दुकानों के सामने सुबह से लम्बी-लम्बी लाइनें 5 किलो मुफ्त अनाज लेने वालों की लग जाती है। नीति आयोग के मुताबिक मध्यप्रदेश, राजस्थान और बिहार में गरीबी सबसे ज्यादा घटी है और वही नीति आयोग यह भी लिख रहा है कि बिहार में 42.20 प्रतिशत आबादी को पर्याप्त पोषण उपलब्ध नहीं है। म.प्र. 34.63 प्रतिशत और राजस्थान में 34.09 प्रतिशत आबादी कुपोषित है। यह कैसी विचित्र रपट है कि जो कुपोषित को भी सम्पन्नता की सूची में मानती है। इसके मुताबिक गाँवों में गरीबी दर 59 प्रतिशत से घटकर 19.28 प्रतिशत रह गई है। और शहरों में 8.65 प्रतिशत से घटकर 5.27 प्रतिशत रह गई है। नीति आयोग के मुताबिक जब देश की कुल आबादी का 15 प्रतिशत निर्धन है याने लगभग 20 करोड़ लोग तो फिर 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार 5-5 किलो मुफ्त राशन क्यों बांट रही है। नीति आयोग की रपट की यह विसंगति बताती है कि रपट के निष्कर्ष तो भारत सरकार ने पहले ही तय कर दिये थे और निष्कर्षो को तर्क देने के लिये रपट तैयार की गई है।

पिछले दिनों हुई कुछ घटनाओं का मैं ज़िक्र करना चाहूंगा जो देश में गरीबी, लाचारी, भुखमरी और निर्धनता के असली हालातों को सामने लाती है। 19 जुलाई 2023 को तमिलनाडु के सेलम की एक महिला ने बस के आगे कूदकर जान दे दी। इसकी वजह यह थी कि उसे किन्ही लोगों ने बताया था कि सड़क हादसे में मौत के बाद मरने वालों को 45,000 रूपये का अनुदान मिलता है। यह गरीब महिला कलेक्ट्रेट में सफाईकर्मी थी और अपने बेटे को पढ़ाने के लिये इस महिला के पास फीस चुकाने के लिये पैसा नहीं था। उसने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से कर्ज माँगा था परन्तु उसे कर्ज नहीं मिल सका तो दुर्घटना से मरकर जो 45000 रूपये का अनुदान मिलेगा उससे बेटे की कॉलेज की फीस चुक जायेगी। इसके लिये उसने बस के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। उसका पति तो पूर्व में ही मर चुका था। क्या नीति आयोग नियंत्रक निर्माता इस घटना का विश्लेषण अपने आंकड़ों के प्रकाश में करेंगे। ऐसी एक नहीं सैकड़ों घटनायें रोज़ घट रही है। जिनमें से अधिकांश की सूचना मीडिया तक पहुंच नहीं पाती । म.प्र. में ऑनलाईन जॉब देने वालों ने गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों

नीति आयोग के मुताबिक मध्यप्रदेश, राजस्थान और बिहार में गरीबी सबसे ज्यादा घटी है और वही नीति आयोग यह भी लिख रहा है कि बिहार में 42.20 प्रतिशत आबादी को पर्याप्त पोषण उपलब्ध नहीं है। म.प्र. 34.63 प्रतिशत और राजस्थान में 34.09 प्रतिशत आबादी कुपोषित है। यह कैसी विचित्र रपट है कि जो कुपोषित को भी सम्पन्नता की सूची में मानती है। इसके मुताबिक गाँवों में गरीबी दर 59 प्रतिशत से घटकर 19.28 प्रतिशत रह गई है। और शहरों में 8.65 प्रतिशत से घटकर 5.27 प्रतिशत रह गई है। नीति आयोग के मुताबिक जब देश की कुल आबादी का 15 प्रतिशत निर्धन है याने लगभग 20 करोड़ लोग तो फिर 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार 5-5 किलो मुफ्त राशन क्यों बांट रही है।

को ऑनलाईन लोन लेने के लिये बाध्य करना शुरूकिया। इस रैकेट के परिणाम बड़े गंभीर हो रहे है। म.प्र. की राजधानी भोपाल के नीलबढ़ के शिव विहार कॉलोनी में रहने वाले भूपेन्द्र विश्वकर्मा ने 13 जुलाई की रात अपने दो बेटों रितुराज और ऋषिराज को कोल्ड ड्रिंक में सल्फास मिलाकर खिलाया और उनके मरने के बाद अपनी पत्नी रितु के साथ फँसी लगाकर जान दे दी। भूपेन्द्र टाटा ए.आई.जी. कम्पनी में काम करते थे और उनके पास कोलम्बिया की किसी कंपनी का संदेश ऑनलाईन जॉब के लिये आया जिनमें वे ऑनलाईन जॉब के लिये तैयार हो गये तथा कंपनी ने उन्हें ऑनलाईन लोन भी दिया और फिर 17 लाख रूपये की रिकवरी बताने लगे। जबकि भूपेन्द्र का कहना था कि मैंने कोई लोन नहीं लिया। भूपेन्द्र ने अपने सुसाईड नोट लिखा है वह इतना मार्मिक है कि जिसे पढ़कर किसी भी व्यक्तिकी आंखों में आँसू बह जाए। उन्होंने लिखा है कि हमारी आखरी इच्छा है कि हमारा सामूहिक दाह संस्कार करें, पोस्टमार्टम न करें, ताकि हम चारों साथ रहें। क्या इससे भयावह गरीबी की और कोई घटना हो सकती है।

एक तरफ यह गरीबी की हालत है और दूसरी तरफ यह प्रचार किया जाता है कि दुनिया में हम सबसे बड़ी आबादी वाले यानि 142 करोड़ वाले बनकर, चीन को पीछे छोड़ चुके हैं। कुछ लोग इस आबादी की वृद्धि को महान घटना मानते हैं और सत्ता तंत्र में बैठे लोग यह प्रचार करते हैं कि इस आबादी की वृद्धि से देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन होगा। यह आबादी ही हमारी सबसे बड़ी संपदा है। यह कहने वाले लोग यह भूल जा रहें हैं कि देश की बड़ी हुई आबादी के कितने भयावह परिणाम देश व समाज पर पड़ रहे हैं। बेरोजगारों की जो एक बड़ी सेना खड़ी हो रही है। उसके सामने क्या भविष्य है? या तो वह अपराधी बनेंगे या आत्महत्या करेंगे। सरकार ने हर सरकारी क्षेत्र को या तो समाप्त कर दिया या फिर निजी हाथों में दे दिया। जिसके परिणामस्वरूप रोजगार याने स्थाई और समुचित रोजगार घटे हैं। मैं मान लेता हूँ आबादी की जरूरतों की पूर्ति के लिये होटल, और अन्य प्रकार के स्वरोजगार बढ़े हैं जिससे आबादी के एक हिस्से को भरपेट रोटी आदि का इंतजाम हुआ है। परन्तु इसमें एक विसंगति यह भी है कि रोजगार और योग्यता का कोई संबंध नहीं है। मैं अनेक ऐसे नौजवानों को जानता हूं जो बी.ई. पास कर ठेकेदारों के यहां चौकीदारी जैसा काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो चाय-पान की दुकान चला रहे हैं। निसंदेह चाय-पान की दुकान से उनका पेट भरेगा परन्तु क्या इंजीनियरिंग पास नौजवान की क्षमता का यह समुचित उपयोग है। जिस प्रकार देश में पूँजी जमा करने वाली फर्जी कंपनियों की बाढ़ आई है जो पहले बड़े-बड़े लालच व सपने दिखाती है और फिर पैसे लेकर भाग जाती है। इनका माध्यम यही बेरोजगार बन रहे हैं। वे स्थानीय लोग होते हैं, और अपने क्षेत्र आदि संपर्क का प्रयोग कर वह लोगों को इन कम्पनियों में पूँजी निवेश के लिये

प्रेरित करते हैं। क्योंकि इसी जमा राशि के दम पर उनकी वेतन व तरक्की तय होती है। जब पैसे वापिसी का समय आता है तो कंपनी के मालिक ताला डालकर भाग जाते हैं और यह बीच के नौजवान अपराधों में फंसते एवं हवालात जाते हैं। क्या यह कोई रोजगार है? परन्तु नीति आयोग व सरकार की परिभाषा में नैतिक-अनैतिक कानूनी-गैर कानूनी, सभी काम रोजगार में शामिल है। ऐसा न हो कि कोई दिन सरकारें चोरी, डकैती, लूटमारी करने वालों को रोजगार में शामिल कर लें। सैक्स वर्कर के नाम पर पेट भरने को लाचार बहनें तो पहले ही सरकारी रोजगार संख्या में शामिल है। याने एक लाचार वैश्यावृति सरकार के लिये रोजगार है।

इसके अलावा इस बढ़ी हुई आबादी का प्रभाव प्रकृति और पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। स्वाभाविक है कि बड़ी आबादी के लिये ज्यादा मकान, पानी, बिजली, सड़क यातायात के साधन और इसके लिये जमीनें चाहिये। देश में कृषि का रकबा क्रमशः घट रहा है। प्रतिवर्ष लाखों एकड़ कृषि की जमीन शहरीकरण निगल रहा है। गाँव से शहरों की ओर भागना लोगों की लाचारी है। क्योंकि जब रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिल सकता है वह शहरों में है तो आदमी शहरों की ओर भागेगा। अब तो स्थिति यह है कि गाँवों में भीख भी नहीं मिलती। हाँ अंधविश्वास के कारण कथावाचकों, बाबाओं को भले लोग पैसा व चढ़ावा चढ़ाते हो। भिखारियों को भीख नहीं देते। भिखारियों की फौज तो शहरों में ही मिलेगी। शहरों के मंदिर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, बाजार की सड़के हो भिखारियों से भरी पड़ी। हो सकता कोई दिन सरकार भीख माँगने को भी रोजगार मान ले। जब वैश्यावृति को रोजगार मान लिया गया तो भीख माँगने को भी रोजगार मान लें। जब दलाली को कमीशन एजेन्ट मानकर रोजगार मान लिया तो हर सही या गलत, नैतिक-अनैतिक काम को रोजगार सरकार बना सकती है।

मैं प्रधानमंत्री और नीति आयोग के उप सभापति से अनुरोध करूंगा कि वह इन तथ्यों के संदर्भ में अपने अध्ययन की जांच कराये और रपट को संशोधित करें। समस्याओं को छुपाने से समस्या का निदान नहीं होगा बल्कि समस्या को देश के सामने रखना, देश को साथ लेकर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अंत में इतना और कहूंगा कि आबादी यह न सरकार, न देश की बल्कि यह एक लाचारी है कि अगर सरकार भविष्य को बनाना चाहती है तो उसे आबादी के नियंत्रण पर निष्पक्ष भाव से काम शुरू करना होगा। वरना हम पतन के किस कगार तक जायेंगे यह भविष्यवाणी करना आज संभव नहीं है और उचित भी नहीं है।

NDA बनाम I.N.D.I.A.

समता पाठक

पिछले नौ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा नीत एनडीए गठबंधन को चुनौती देने के लिए कांग्रेस सहित देश के 26 विपक्षी दलों के नेताओं ने एक नए राजनीतिक गठबंधन बनाने की घोषणा की है। बेंगलुरु में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हुए दलों ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के स्थान पर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) के नाम पर एक नया गठबंधन बनाया है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन के संयोजक की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। विपक्ष का कहना है कि उनका इंडिया गठबंधन पहले के यूपीए की तुलना में अधिक मजबूत है। इसमें ऐसे राजनीतिक दल भी शामिल है जो अभी तक आपस में एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। कांग्रेस के धुर विरोधी रहे अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में शामिल है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कट्टर विरोधी वामपंथी दल व कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन में एक साथ शामिल हुए है। केरल में आमने-सामने चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस व वामपंथी दल एकजुट नजर आ रहे हैं।

माना जा रहा है कि विपक्ष कुछ कर ले आने वाले लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, मराठा क्षत्रप शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला, हेमंत सोरेन, एमके स्टालिन, सीताराम येचुरी, डी राजा, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती सहित बहुत से वरिष्ठ नेता शामिल है। इंडिया गठबंधन के पास अभी लोकसभा की कुल 142 सीटें हैं। मगर गठबंधन में शामिल 11 दलों का तो लोकसभा में एक भी सांसद नहीं हैं।

इस गठबंधन में शामिल पार्टियों की अभी देश के 11 प्रांतों में सरकार चल रही है। जिनमें कांग्रेस की चार प्रदेशों कर्नाटका, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में वहीं जनता दल (यूनाइटेड) व राष्ट्रीय जनता दल की बिहार में, तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में, झारखंड मुक्तिमोर्चा की झारखण्ड में, आम आदमी पार्टी की दिल्ली व पंजाब में, द्रविड़ मुनेत्र कषगम की तमिलनाडु मे,

वामपंथी दलों की केरल में सरकार है।

इंडिया गठबंधन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कषगम, आम आदमी पार्टी (आप), जनता दल (यूनाइटेड), राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार), शिवसेना (यूबीटी), समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल (कमेरावादी), जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा)

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी), रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी), ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, मरु मलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कझगम (एमडीएमके), विदुथालाई चिरु थैगल कच्ची (वीसीके), कोंगुनाडु मक्कल देसिया काची (केएमडीके), मनिथानेय मक्कल काची (एमएमके), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस (मणि), केरल कांग्रेस (जोसेफ) शामिल है।

इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेसको छोड़ कर अन्य राजनीतिक दलों का अपने-अपने प्रदेशों में ही प्रभाव है। यदि इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल अपने पुराने मतभेद भुलाकर एकजुटता से चुनाव लड़ते हैं और आपसी समझदारी से सीटों का बंटवारा कर भाजपा के समक्ष एक ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारते हैं तो निश्चित रूप से भाजपा को कड़ी चुनौती दे पाएंगे।

हालांकि इंडिया गठबंधन में 26 राजनीतिक दल तो शामिल हो गए हैं। लेकिन उनमें अभी भी चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर संशय बरकरार है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली व पंजाब को कांग्रेस उनके लिए छोड़ दे। बदले में अन्य प्रदेशों में आप कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारेगी। यही स्थिति पश्चिम बंगाल में है जहां ममता बनर्जी चाहती है कि कांग्रेस व वामपंथी दल उनके खिलाफ चलाए जा रहे अपने राजनीतिक अभियानों को रोककर उनका सहयोग करें ताकि भाजपा को हराया जा सके।

ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल में वैसे भी वामपंथी दलों व कांग्रेस का आधार समाप्त हो गया है। ऐसे में यदि वह तृणमूल कांग्रेस को सहयोग करते हैं तो पूरे बंगाल में विपक्षी दलों का प्रभाव बढ़ने से भाजपा का सफाया हो सकता है। पश्चिम बंगाल में 34 वर्षों तक लगातार वाम मोर्चे का शासन रहा था। वाम मोर्चे को हराकर ही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी बंगाल में सत्तारूढ़ हुई है।

ऐसे में वामपंथी दलों को लगता है कि यदि उन्होंने पश्चिम बंगाल को ममता दीदी के हवाले कर दिया तो वहां उनका रहा सहा जनाधार भी समाप्त हो जाएगा। केरल में भी कांग्रेस व वामपंथी दल आमने-सामने चुनाव लड़ते हैं। मगर देश के अन्य प्रदेशों में मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ममता बनर्जी व अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस से केरल की तरह ही सामंजस्य चाहते हैं।

पटना में आयोजित हुयी 16 राजनीतिक

दलों की मीटिंग से भाजपा में भी हलचल मच गई थी। इसी कारण बेंगलुरु मीटिंग के दिन ही भाजपा ने नई दिल्ली में एनडीए गठबंधन की बैठक का आयोजन किया और उसमें छोटे बड़े मिलाकर 38 दलों के नेताओं को शामिल किया था। इतना ही नहीं उस बैठक में पूरे समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे थे। केंद्र में दूसरी बार सत्तारूढ़ होने के बाद भाजपा ने शायद पहली बार एनडीए गठबंधन की बैठक बुलाई थी।

वह भी उस स्थिति में जब उनको लगने लगा कि विपक्षी दलों का गठबंधन राजनीतिक रूप से उनके गठबंधन से बड़ा होने जा रहा है। भाजपा ने एनडीए की बैठक में ऐसे दलों को भी शामिल किया जो हाल ही में एनडीए से जुड़े थे। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों के नेताओं की बातें सुनी और उन पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की बात भी कही।

विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और उसका पूरे देश में प्रभाव भी है। ऐसे में कांग्रेस के नेता चाहेंगे कि इस गठबंधन की कमान कांग्रेस के हाथों में रहे। जिससे सभी दलों में समन्वय बनाकर आगे बढ़ा जा सके। वैसे भी इंडिया गठबंधन में शामिल अधिकांश राजनीतिक दल पहले से ही यूपीए में शामिल थे। जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही थी। हालाँकि अरविन्द केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जैसे नेता नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस को नए बने गठबंधन कि कमान मिले।

देश के विपक्षी दलों की आपसी फूट का फ़ायदा उठाकर सरकार अपनी मर्जी से काम करती है। राजनीति में कहा जाता है कि जिस देश या प्रदेश में विपक्षी दल मजबूत नहीं होंगे वहां की सरकारें मनमानी करेगी। इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों के आगाज को देख कर तो लगता है कि अगले चुनाव तक उनकी एकजुटता बनी रहे।

कांग्रेस पार्टी ने अपने दिल्ली व पंजाब के नेताओं के विरोध के बावजूद दिल्ली सरकार पर केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के विरोध में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर संसद में समर्थन देने की घोषणा कर जता दिया है कि विपक्ष की मजबूती के लिए वह कितना भी झुकने को तैयार है। मीटिंग से पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों को अल्टीमेटम दे दिया था कि यदि कांग्रेस संसद में उनके समर्थन कि घोषणा नहीं करती है तो वो अगली मीटिंग में शामिल नहीं होंगे।

आप के दबाव के चलते कांग्रेस को झुकना पड़ा। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेता जब तक एक दूसरे कि भावना का सम्मान नहीं करेंगे तब तक इस गठबंधन का सफल होना मुश्किल लगता है।

चिंता का विषय है जनसंख्या विस्फोट

जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम अब खुलकर दिखने लगे हैं। जैसे, एक भूखा बेजुबान पशु खाने पर झपट्टा मारता है, स्थिति इंसानों में भी कुछ ऐसी ही होने लगी है। गांव-देहातों में मात्र गज भर जमीन के लिए खुलेआम कत्ल होने लगे हैं। शहरों में पार्किंग को लेकर सिर फटने शुरू हो गए हैं। युवा पेट पालने के लिए धक्के खाने पर मजबूर हैं। अब देखिए ना, एक चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की फौज लाइनों में लगने लगी है।

अनद्या वर्मा

जनसंख्या में हम नंबर वन हो गए हैं, जो उपलब्धि नहीं है, बल्कि घोर चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत को जनसंख्या आबादी के लिहाज से अव्वल घोषित कर दिया है, जबकि इस पायदान पर काफी समय से चीन ही रहा। लेकिन अब वो दूसरे नंबर पर है। बेहताशा बढ़ती जनसंख्या ने न केवल वर्तमान विकास क्रम को प्रभावित कर रही है, बल्कि भविष्य की कई चुनौतियां को भी खड़ा कर दिया है। हिंदुस्तान में सुगबुगाहट बीते कुछ महीनों से है कि जनसंख्या रोकने की योजना बन चुकी है जिसका खुलासा जल्द होने वाला है। बताया जा रहा है कि यूसीसी के भीतर ही

जनसंख्या नियंत्रण का मसौदा भी शामिल हैं। हालांकि इसको लेकर अभी भ्रम की स्थिति बनी हुई। फिलहाल कानून के ड्राफ्ट के संबंध में अभी तक खुलकर सरकार ने भी पत्ते नहीं खोले हैं। पर, इतना जरूर है, अगर यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण का प्रावधान होगा, तो इससे बढ़ती आबादी पर कुछ अंकुश जरूर लग सकेगा।

चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष सभी की निगाहें समान नागरिक संहिता की तरफ हैं

बहरहाल, जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा बहुत पेचिदा होता चला जा रहा है, कुछ समर्थन में हैं तो कई विरोध में खड़े हैं? समय की मांग यही है किसी की परवाह किए बिना केंद्र को इस मसले पर गंभीर होना पड़ेगा। क्योंकि बगैर सरकारी सख्ती के कोई हल निकलने वाला नहीं? विगत बीते चार दशकों में जन आबादी में जिस तेजी से बढ़ोतरी हुई, उसने सबकुछ तहस-नहस कर दिया। जनसंख्या ने ही साधन, संसाधन, जमीन, हक-हकूक, रोजगार व काम-धंधों पर प्रहार किया है। हिंदुस्तान की आबादी विकराल रूप ले चुकी है।

जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम अब खुलकर दिखने लगे हैं। जैसे, एक भूखा बेजुबान पशु खाने पर झपट्टा मारता है, स्थिति इंसानों में भी कुछ ऐसी ही होने लगी है। गांव-देहातों में मात्र गज भर जमीन के लिए खुलेआम कत्ल होने लगे हैं। शहरों में पार्किंग को लेकर सिर फटने शुरू हो गए हैं। युवा पेट पालने के लिए धक्के खाने पर मजबूर हैं। अब देखिए ना, एक चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की फौज लाइनों में लगने लगी है।

बढ़ती आबादी से रोजगार-धंधे सिमट गए हैं। आवासीय इलाके व सड़कें इंसानों और वाहनों से खचाखच भर चुकी हैं। पार्किंग फुल हैं, घरों के आंगन सिमट गए हैं, आवासीय जगहें कम हो गई हैं, इसी कारण फ्लैट संस्कृति का चलन लागू हो गया है। इसलिए जनसंख्या विस्फोट को रोकना निहायत ही जरूरी हो गया है। इसमें भला किसी एकवर्ग या एक समुदाय का फायदा नहीं, बल्कि सबका भला है।

सरकार का स्लोगन हम दो हमारे दो भी बढ़ती आबादी के समाने फीका पड़ चुका है। इसे कुछों ने अपनाया, तो कईयों ने नकारा? भारत के अलावा इथियोपिया-तंजानिया, संयुक्त राष्ट्र, चीन, नाइजीरिया, कांगो,

पाकिस्तान, युगांडा, इंडोनेशिया व मिश्र भी ऐसे मुल्क हैं जहां की स्थिति भी कमोबेश हमारे ही जैसी है। लेकिन इन कई देशों में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कानून अमल में आ चुके हैं।

कई देशों में दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सरकारी सुविधाओं से वंचित करने का फरमान जारी हो चुके हैं। जनगणना-2011 के मुताबिक भारत की आबादी 121.5 करोड़ थी जिनमें 62.31 करोड़ पुरूष और 58.47 करोड़ महिलाएं शामिल थीं। लेकिन अब 140 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश में है जिसकी आबादी पाकिस्तान की जनसंख्या को भी पार कर गई है।

वहीं, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अब भी सिक्किम ही है। जनसंख्या नियंत्रण पर जब भी कानून बनाने की मांग उठती है,उसे सियासी मुद्दा बना दिया जाता है। जबकि, इस समस्या से आहत सभी हैं। पढ़ा-लिखा हिंदु-मुसलमान, सिख-ईसाई सभी समर्थन में हैं कि इस मसले पर मुकम्मल प्रयास होने चाहिए। समूचा हिंदुस्तान जनसंख्या विस्फोट का भुगतभोगी है। बेरोजगार युवा तनाव में हैं। कुछ गलत रास्तों पर भी चल पड़े हैं।

एनसीआरबी के ताजे आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि हर तरह के अपराधों में युवाओं की संख्या अब बढ़ रही है जिसमें ब्लैकमेलिंग, लूटपाट, चोरी, रंगबाजी आदि कृत्य शामिल हैं। बढ़ती आबादी को देखकर प्रबुद्ध वर्ग दुखी है, वह सहूलियतें चाहते हैं, सामान अधिकार चाहते हैं, खुली फिज़ाओं में सांस लेना चाहते हैं, सभी को घरों की छत और रोजगार मिले इसकी ख्वाहिशें सभी की हैं।

युवाओं को जरूरत के हिसाब से जॉब मुहैया हां, डिग्री लेकर सड़कों पर घूमना न पड़े। इसलिए समूचा शिक्षित अल्पसंख्यक वर्ग भी जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में हैं। हां, उनका एक धड़ा इसके खिलाफ है, जो जनसंख्या बढ़ोतरी को कुदरत का वरदान मानता है। उसे रोकने को बुरा मानता है। दरअसल, ऐसे लोगों की मानसिकता को हमें बदलने की जरूरत है।

पढ़ा लिखा मुसलमान भी भविष्य में होने वाले खतरों से वाकिफ हो चुका है। वक्तकी मांग यही है, जनसंख्या चाहें यूसीसी के माध्यम से रूके या फिर किसी अलहदा कानून से, रूकना चाहिए। इसके लिए सभी पक्ष-विपक्षों को एक मंच पर आने की जरूरत है। समाज को इस मसले पर सरकार का साथ देना चाहिए।

Global Warming its effects and challenge for America

Shefali Vaibhav

Curbing dangerous climate change requires very deep cuts in emissions, as well as the use of alternatives to fossil fuels worldwide. The good news is that we've started a turnaround: CO2 emissions in the United States actually decreased from 2005 to 2014, thanks in part to new, energy-efficient technology and the use of cleaner fuels. And scientists continue to develop new ways to modernize power plants, generate cleaner electricity, and burn less gasoline while we drive. The challenge is to be sure these solutions are put to use and widely adopted.

How is global warming linked to extreme weather?

Scientists agree that the earth's rising temperatures are fueling longer and hotter heat waves, more frequent droughts, heavier rainfall, and more powerful hurricanes. In 2015, for example, scientists said that an ongoing drought in California the state's worst water shortage in 1,200 years had been intensified by 15 percent to 20 percent by global warming. They also said the odds of similar droughts happening in the future had roughly doubled over the past century. And in 2016, the National Academies of Science, Engineering, and Medicine announced that it's now possible to confidently attribute certain weather events, like some heat waves, directly to climate change.

The earth's ocean temperatures are getting warmer, too which means that tropical storms can pick up more energy. So global warming could turn, say, a category 3 storm into a more dangerous category 4 storm. In fact, scientists have found that the frequency of North Atlantic hurricanes has increased since the early 1980s, as well as the number of storms

that reach categories 4 and 5. In 2005, Hurricane Katrina—the costliest hurricane in U.S. history struck New Orleans; the second-costliest, Hurricane Sandy, hit the East Coast in 2012.

The impacts of global warming are being felt across the globe. Extreme heat waves have caused tens of thousands of deaths around the world in recent years. And in an alarming sign of events to come, Antarctica has been losing about 134 billion metric tons of ice per year since 2002. This rate could speed up if we keep burning fossil fuels at our current pace, some experts say, causing sea levels to rise several meters over the next 50 to 150 years.

What are the other effects of global warming?

Each year, scientists learn more about the consequences of global warming, and many agree that environmental, economic, and health consequences are likely to occur if current trends continue. Here's just a smattering of what we can look forward to:

- Melting glaciers, early snowmelt, and severe droughts will cause more dramatic water shortages and increase the risk of wildfires in the American West.
- Rising sea levels will lead to coastal flooding on the Eastern Seaboard, especially in Florida, and in other areas such as the Gulf of Mexico.
- Forests, farms, and cities will face troublesome new pests, heat waves, heavy downpours, and increased flooding. All those factors will damage or destroy agriculture and fisheries.
- Disruption of habitats such as coral reefs and Alpine meadows could drive many plant and animal species to extinction.
- Allergies, asthma, and infectious disease outbreaks will become more common due to increased growth of pollen-producing ragweed, higher levels of air pollution, and the spread of conditions favorable to pathogens and mosquitoes.

Where does the United States stand in terms of global-warming contributors?

In recent years, China has taken the lead in global-warming pollution, producing about 28

percent of all CO_2 emissions. The United States comes in second. Despite making up just 4 percent of the world's population, we produce a whopping 16 percent of all global CO_2 emissions as much as the European Union and India (third and fourth place) combined. And America is still number one, by far, in cumulative emissions over the past 150 years. Our responsibility matters to other countries, and it should matter to us, too.

Is the United States doing anything to prevent global warming?

We've started. But in order to avoid the worst effects of climate change, we need to do a lot more together with other countries to reduce our dependence on fossil fuels and start using clean energy instead.

In 2015, the U.S. Environmental Protection Agency pledged to reduce carbon pollution from our power plants by nearly a third by 2030, relative to 2005 levels, through its Clean Power Plan. But fast-forward to 2017, and under the Trump Administration, the EPA proposed repealing this critical tool for curbing climate change. Likewise, while under the Obama administration, the U.S. Department of Transportation proposed carbon pollution and fuel economy standards intended to cut emissions through the 2020s, under Trump administration, the DOT is working to roll back those clean vehicle safeguards that protect the climate and our health.

Fortunately, state leaders—including in car country itself recognize that clean transportation must remain a priority if we are to address the costly risks of climate change and protect public health. And regional efforts around the country are helping to boost the electric car market, which saw an increase in sales for 2017 over 2016. Our clean energy economy is growing too, despite federal efforts to derail it. In 2016, wind employment grew by 32 percent and solar jobs

increased by 25 percent.

Globally, at the United Nations Conference on Climate Change in Paris, 195 countries including the United States, at the time agreed to pollution-cutting provisions with a goal of preventing the average global temperature from rising more than 1.5 degrees Celsius above preindustrial times. (Scientists say we must stay below a two-degree increase to avoid catastrophic climate impacts.)

To help make the deal happen, the Obama administration pledged $3 billion to the Green Climate Fund, an international organization dedicated to helping poor countries adopt cleaner energy technologies. Under the terms of the Paris agreement, participating nations will meet every five years, starting in 2020, to revise their plans for cutting CO2 emissions. Beginning in 2023, they will also have to publicly report their progress.

While in 2017, President Trump announced the country's withdrawal from the Paris climate agreement and to eliminate "harmful and unnecessary policies such as the Climate Action Plan," Americans are forging ahead without him. Through initiatives like the United States Climate Alliance, the Regional Greenhouse Gas Initiative, We Are Still In, and Climate Mayors, state, business, and local leaders have pledged to honor and uphold the goals of the Paris Agreement. More than 25 cities in 17 states, with populations totaling more than 5 million have adopted resolutions that will enable them to get 100 percent of their electricity from renewable sources like wind and solar.

Even better, a new initiative by former New York City mayor Michael Bloomberg gives the urban layer of this movement a boost. He's asked mayors from the 100 most populous cities in the country to share their plans for making their buildings and transportation systems run cleaner and more efficiently. The 20 that show the greatest potential for cutting the dangerous carbon pollution that's driving climate change will share a total of $70 million in technical assistance funding provided by Bloomberg Philanthropies and partners.

Is global warming too big of a problem for me to help tackle?

Wondering how to stop global warming? Reduce your own carbon footprint by following a few easy steps. Make conserving energy a part of your daily routine and your decisions as a consumer. When you shop for new appliances like refrigerators, washers, and dryers, look for products with the government's Energy Star label; they meet a higher standard for energy efficiency than the minimum federal requirements. When you buy a car, look for one with the highest gas mileage and lowest emissions. You can also reduce your emissions by taking public transportation or carpooling when possible.

And while new federal and state standards are a step in the right direction, much more needs to be done. Voice your support of climate-friendly and climate change preparedness policies, and tell your representatives that transitioning from dirty fossil fuels to clean power should be a top priority because it's vital to building healthy, more secure communities.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.